

● वर्ष-6
● अंक-73
रायपुर, शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-३ रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम्।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>>

मांझी-चालकी की परंपरा का...

पैरा एशियाड में दमदार प्रदर्शन जारी एथलेटिक्स में जीते पांच स्वर्ण



भारत ने पार किया 80 पदकों का आंकड़ा

नागोया । भारतीय पैरा एथलीटों ने आइची-नागोया में जारी पैरा एशियन गेम्स में दमदार प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रखा। भारत ने गुरुवार को कुल 26 पदक अपने नाम किए और पदकों की संख्या 88 पहुंचा दी है। भारत के पैरा एथलीटों ने लगातार दूसरे दिन पांच स्वर्ण पदक अपने नाम किए जिससे पदक तालिका में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। शीतल देवी ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में एक और यादगार प्रदर्शन किया है। उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में सिंगापुर की नूर स्याहिदा अलीम को 142-139 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पैरा-आर्चर ने चार अंकों से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और पिछले एशियन पार गेम्स में जीते गए अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत के साथ ही आइची-नागोया में शीतल का शानदार सफर पूरा हुआ। इसके अलावा, शीतल ने पायल नाग के साथ मिलकर महिलाओं के कंपाउंड डबल्स में सिल्वर मेडल भी जीता।

भारतीय तीरंदाज स्वाति चौधरी ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत डब्ल्यू1 स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। वह इस वर्ग में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। स्वाति ने फाइनल में 4-2 की बढ़त बनाई, लेकिन चीन की सेन मेंगकान ने वापसी करते हुए 6-4 से मुकाबला जीत लिया।

पैरा बैडमिंटन में भारत को मिले पदक पैरा बैडमिंटन में भारत को दो जोड़ियों ने कांस्य पदक जीते। मिश्रित युगल एसएच6 वर्ग में कृष्णा नागर और नित्या श्री को सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की रीना मालीना और सुब्बान के खिलाफ हार मिली। इसके बावजूद भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। वहीं, मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में मनीषा रामदास और प्रमोद भगत ने भी कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया

विधान परिषद चुनाव से पहले सपा का धमकाने का आरोप

लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीट पर 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान से पहले अपने समर्थक मतदाताओं को धमकाने और मतदान से रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले में तत्काल कार्रवाई करने और मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा भयमुक्त माहौल में कराने की मांग की है। पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर यह ज्ञापन साँपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है प्रदेश के कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव समेत 72 जिलों में मतदान के दौरान सपा समर्थक मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों और भाजपा पदाधिकारियों के इशारे पर पुलिसकर्मी सपा समर्थकों को चिह्नित कर उन्हें मतदान के दिन घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे रहे हैं। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि समर्थकों को फजी मुकदमों में फंसाने और गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है।

वोट चोरी एक साबित हकीकत : जयराम रमेश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तोखा हमला करते हुए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को उन पर झूठ फैलाकर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप



लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का इकोसिस्टम हताशा और घबराहट में है। कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने केंद्र सरकार पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि वोट चोरी एक साबित हो चुकी सच्चाई है। एक्स पर एक पोस्ट में जयराम ने लिखा वोट चोरी एक साबित हो चुकी सच्चाई है। ईसीआई (चुनाव आयोग) के अपने आंकड़ों के अनुसार, 10 करोड़ से अधिक भारतीयों के सामने अपना संवैधानिक वोटिंग अधिकार खोने का खतरा है। ईसीआई ने नए मतदाताओं के लिए रूकावटें पैदा करने के लिए फॉर्म 6 में गैर-कानूनी तरीके से बदलाव किए हैं। इसने चुनिंदा लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए, उन्होंने कहा कि सीईसी ने सभी कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनारा कर दिया है।

रक्षा सहयोग बढ़ेगा, लेकिन ठोस सौदे का इंतजार

पोलैंड ने भारत के साथ मिलकर चल दी बड़ी कूटनीतिक चाल

नीरज कुमार दुबे

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए जारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों के बीच यूक्रेन के पड़ोसी और रूस के साथ टकरावपूर्ण संबंधों के लिए पहचाने जाने वाले पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों ने व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और रक्षा समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। खास तौर पर रक्षा उद्योग में साझेदारी, संयुक्त अनुसंधान और सह-उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ने के फैसले ने इस यात्रा को रणनीतिक रूप से

महत्वपूर्ण बना दिया है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि पोलैंड के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग रूस के साथ भारत के दशकों पुराने और मजबूत रक्षा संबंधों को किस हद तक प्रभावित करेगा ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की आज हुई व्यापक बातचीत ने भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की कोशिश की है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय करने के साथ रक्षा उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, (एआई), अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। हम आपको याद दिला दें

कि अगस्त 2024 में मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था और 2024-2028 की संयुक्त कार्ययोजना अपनाई गई थी। टस्क की 21 से 23 अक्टूबर तक की भारत यात्रा इसी साझेदारी की मध्यावधि समीक्षा के बाद आगे की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। साथ ही पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 प्रमुख द्विपक्षीय प्रतिनिधियों का आना बताता है कि वारसां भारत को केवल राजनीतिक सहयोगी नहीं, बल्कि निवेश, उत्पादन और तकनीकी साझेदारी के बड़े बाजार के रूप में देख रहा है।

हम आपको बता दें कि रक्षा क्षेत्र में



दोनों देशों ने नियमित संस्थागत संवाद जारी रखने और रक्षा उद्योगों के बीच व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके लिए डिफेंस इंडस्ट्री डायलॉग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कंपनियों के बीच संपर्क बढ़ाने तथा पारस्परिक सहमति से तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, सह-विकास और सह-उत्पादन की

संभावनाएं तलाशने की योजना है।

साथ ही पोलैंड के वित्त मंत्री आंद्रेज दोमान्स्की ने यात्रा से पहले भारतीय कंपनियों के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास में साझेदारी की इच्छा जताई थी।

उनका कहना था कि पोलैंड भारतीय बाजार को रक्षा उपकरणों का आपूर्ति करने के साथ तकनीकी सहयोग भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन फिलहाल संयुक्त घोषणा में किसी खास हथियार प्रणाली, सैन्य उपकरण, तकनीक हस्तांतरण या भारत में रक्षा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का विवरण नहीं दिया गया है। लिहाजा, रक्षा सहयोग का

ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम तो बढ़ा है, लेकिन उसे ठोस सौदों में यह बदलना अभी बाकी है। इसके अलावा, संवेदनशील रक्षा सूचनाओं की सुरक्षा के लिए दोनों पक्षों ने वर्गीकृत सूचनाओं के पारस्परिक संरक्षण और आदान-प्रदान संबंधी समझौते पर जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई है।

आर्थिक मोर्चे पर देखें तो सबसे ठोस घोषणा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने की है। दोनों देशों के बीच 2025 में व्यापार करीब 6.36 अरब डॉलर रहा था। ऐसे में 10 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करना भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, हालांकि संयुक्त बयान में इसके लिए अलग से कोई वार्षिक लक्ष्य या

क्षेत्रवार निवेश समयसीमा घोषित नहीं की गई है। भारत-पोलैंड संबंधों में यह लक्ष्य कारोबार को नई ऊंचाई देने की राजनीतिक प्रतिबद्धता जरूर दर्शाता है। साथ ही मोदी ने पोलिश कंपनियों को भारत में निवेश और परिचालन विस्तार का न्यौता दिया। औद्योगिक मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, बुनियादी ढांचे, खनन, ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा गया है। भारत से मशीनरी, रसायन, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। पोलैंड भारतीय कंपनियों के लिए मध्य और पूर्वी यूरोप के बाजारों तक पहुंच बनाने का प्रवेश द्वार बनाना चाहता है।

युवा अपनी सफलता को राष्ट्र की सेवा से जोड़ें : मुर्मु

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक : राष्ट्रपति

सेवा संकल्प अभियान के रक्तदान महाकुंभ में 2,548 लोगों ने किया रक्तदान, 1,188 महिलाएं भी बनीं मानवता की इस मुहिम में सहभागी

रायपुर। युवा बड़े सपने देखें, अपने विचारों को व्यापक बनाएं और अपनी सफलता को समाज एवं राष्ट्र की सेवा से जोड़ें। परिस्थितियां और चुनौतियां अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक युवा के भीतर कुछ नया करने, बेहतर बनाने और अपनी पहचान स्थापित करने की ललक होनी चाहिए। जब युवाओं के व्यक्तिगत प्रयास सामूहिक और राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ेंगे, तभी देश की प्रगति का मार्ग और अधिक प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में नुआखाई के अवसर पर आयोजित ‘सेवा सम्मान पर्व एवं युवा प्रबोधन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमन डैका और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित थे।



राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने नुआखाई की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नुआखाई मिलन केवल एक सांस्कृतिक समारोह नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध परंपराओं, आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता का उत्सव है। ऐसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और भारतीय जीवन मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि नुआखाई हमारी कृषि परंपरा को सहेजने, प्रकृति के प्रति कुतज्ञता व्यक्त करने और सामुदायिक भावना को मजबूत करने का पर्व है। अन्न केवल हमारी भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि किसान

भाई-बहनों के परिश्रम, धरती की उदारता और प्रकृति के अनमोल उपहार का प्रतीक है। अन्न का सम्मान करना, किसानों के योगदान को स्वीकार करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने युवाओं से कहा कि वे जीवन में सीखना कभी बंद न करें। पुस्तकें पढ़ें, प्रश्न पूछें, नई चीजों को समझें और अपने ज्ञान एवं कौशल को निरंतर विकसित करें। जीवन में लक्ष्य तय करें और चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करें। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा हैं। असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीखकर स्वयं में सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि युवाओं को ज्ञान के साथ विनम्रता, महत्वाकांक्षा के साथ नैतिकता और सफलता के साथ सेवा-भाव को जोड़ना चाहिए। आपका ज्ञान किसी जरूरतमंद के काम आए, आपकी प्रतिभा किसी समस्या का समाधान करे और आपकी सफलता समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बने, तभी उपलब्धि की वास्तविक सार्थकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र का निर्माण केवल बड़े निर्णयों से नहीं होता, बल्कि करोड़ों नागरिकों के छोटे-छोटे ईमानदार प्रयासों से होता है। प्रत्येक युवा जो भी कार्य करे, उसे ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करे। ये गुण विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं के योगदान को और सशक्त बनाएंगे।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। देश की आधी आबादी को आगे बढ़ाए बिना राष्ट्र पूरी क्षमता के साथ प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए महिलाओं से देश और समाज के कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने पुरुषों, विशेषकर युवाओं से कहा कि वे अपनी बहनों और बेटियों को ऐसा वातावरण और अवसर प्रदान करें, जिसमें वे बिना किसी बाधा के अपने सपनों को साकार कर सकें।

सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया पर किया डेब्यू

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधस्पातिवार को सोशल मीडिया में दस्तक देते हुए अपने ‘इंस्टाग्राम’ पेज की शुरुआत की और अपनी पुस्तक की पहली झलक साझा की। उन्होंने पहली बार किसी सोशल मीडिया मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वह अब तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए थीं। उनके वीडियो संदेश या बयान पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी किए जाते रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आने के तुरंत बाद सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी वाद्रा और कांग्रेस के आधिकारिक



अकाउंट को ‘फॉलो’ किया। उनके अकाउंट पर फॉलोअर की संख्या तेजी से बढ़ी और कुछ ही घंटों में यह एक लाख को पार कर गई। राहुल गांधी समेत इंस्टाग्राम पर मौजूद कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के अकाउंट को ‘फॉलो’ किया। कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी का स्वागत किया और उनकी आगामी पुस्तक को लेकर उत्सुकता जाहिर की। सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पोस्ट में आगामी पुस्तक ‘बिलिंगिंग्ग ए जर्नी ऑफ लव’ की प्रतियां प्राप्त करते हुए अपना एक वीडियो साझा किया।

14 भारतीयों को लेकर जा रहे नाव पर सऊदी ने किया हमला

नई दिल्ली। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने लाल सागर में जुकार द्वीप के पास 14 भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक नौका (याट) को निशाना बनाया। उनका कहना है कि यमनी बलों ने नौका पर सवार लोगों को बचा लिया। यह आरोप ऐसे समय में सामने आया है जब सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे पर हमले बढ़ रहे हैं। बुधवार को दम्मम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए एक हमले में दो लोग मारे गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। हूती समर्थित यमनी सशस्त्र बलों के सैन्य प्रवक्ता, ब्रिगेडियर याह्या सरी ने पोस्ट किया शुरुआती जानकारी के अनुसार, सऊदी दुश्मन जुकार द्वीप के पास एक भारतीय नौका को निशाना बना रहा है, जिस पर 14 भारतीय नागरिक सवार हैं। सरी ने कहा कि यमनी सशस्त्र बलों ने भारतीयों को बचाया है। सरी ने एक्स पर पोस्ट किया, लाल सागर में सऊदी दुश्मन द्वारा किया गया यह गैर-जिम्मेदाराना हमला अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए खतरा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सऊदी दुश्मन को ऐसी गैर-जिम्मेदाराना हरकतें करने से रोकना चाहिए।

तिब्बत में भूकंप के तेज झटके रिक्टर पैमाने पर 7.0 रही तीव्रता

ल्हासा। तिब्बत में रात करीब 8०3 बजे भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 173 किलोमीटर की गहराई में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। तीन सितंबर को भी तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई गई थी। भूकंप के झटके दोपहर करीब 1०46 बजे दर्ज किए गए। भूकंप का केंद्र 31.479 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80.370 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। इसकी गहराई जमीन के अंदर करीब 14 किलोमीटर बताई गई। भूकंप का लोकेशन तिब्बत क्षेत्र में दर्ज किया गया। 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने के बाद तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस हुए थे, वहीं इसके बाद तिब्बत को बाढ़ की मार झेलनी पड़ी है। चीन सीमा से जुड़े इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिली है। जनवरी 2025 में तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किये गये थे। इस भीषण भूकंप में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) के अनुसार, सुबह 9.05 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिेक्टर स्केल पर 6.8 मापी गयी थी।



दुर्गा पंडाल में जमकर चले लात-घूसे, पुलिसकर्मों बने रहे तमाशबीन

रायगढ़। जिले में दुर्गा पंडाल के अंदर मारपीट का मामला सामने आया है। चक्रधरनगर चौक पर बीती रात हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आधा दर्जन युवक दो लोगों को जमीन पर गिराकर लात-घूसें से पीटते दिखाई दे रहे हैं। घटना के दौरान मौके पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और उनकी निष्क्रियता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, घटना चक्रधरनगर चौक स्थित दुर्गा पंडाल की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में कुछ युवक दो लोगों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दोनों को जमीन पर गिराकर कई युवक लगातार लात-घूसे बरसाते दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि यह मारपीट काफी देर तक चलती रही। घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के मौके पर मौजूद होने के बावजूद मारपीट जारी रहा। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना को लेकर संबंधित पुलिस थाने को अब तक आधिकारिक सूचना नहीं मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल मारपीट की वजह, इसमें शामिल युवकों की पहचान और पीड़ितों की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

माइंस एरिया में 3 भालुओं की एंट्री से कर्मचारियों में दहशत

बालोद। बालोद जिले के दल्ली राजहरा माइंस एरिया में तीन भालू दिखाई देने से कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। माइंस कर्मचारियों ने भालुओं की मौजूदगी का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष ठाकुर ने लोगों से सतर्क रहने और भालुओं के नजदीक नहीं जाने की अपील की है। माइंस क्षेत्र में भालुओं की मौजूदगी से कर्मचारियों में चिंता बनी हुई है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को देर रात ग्राम भालूकोन्हा स्थित शिव मंदिर परिसर में भालू दिखाई दिया था। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में भालू की हलचल कैद हुई थी।

कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल के सविदा पद पर आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा। विकासित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत जिला सक्ती में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल के सविदा पद पर भर्ती हेतु 05 नवम्बर सायं 05 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि आवेदन जिला पंचायत में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर-चांपा व सक्ती से संपर्क तथा जिले के वेबसाइट <https://janjgir-champa.gov.in/> एवं <https://sakti.cg.gov.in/> का अवलोकन करें।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

दीपावली से पहले एक्शन में खाद्य विभाग, 5 किलो जलेबी नष्ट

खैरागढ़। खैरागढ़ में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। नवागांव चंडी मंदिर क्षेत्र स्थित साहू होटल में निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिलीं। फ़ीजर बंद होने और मिठाइयों के खराब होने की आशंका पर 5 किलो जलेबी नष्ट कराई गई, वहीं मिनी पेड़ा और बालूशाही के नमूने जांच के लिए भेजे गए। आवश्यक सुधार होने तक होटल को बंद करा दिया गया है। दीपावली से पहले विभाग ने मिठाई कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, नवागांव चंडी मंदिर क्षेत्र स्थित मेसर्स साहू होटल में निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की कमी, कालातीत खाद्य सामग्री के विक्रय और भंडारण जैसी खामियां सामने आईं। फ़ीजर बंद मिला और उसमें रखी खाद्य सामग्री के बासी होने की आशंका के चलते विभाग ने तत्काल 5 किलो जलेबी नष्ट करवा दी। कार्रवाई यहीं नहीं रुकी और फिर विभागीय टीम ने होटल से मिनी पेड़ा और बालूशाही के नमूने भी जांच के लिए भेजे।

अबूझमाड़ का छिपा खजाना गारपा जलप्रपात, घने जंगल के बीच प्रकृति का अनछुआ नजारा

नारायणपुर। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद जिन इलाकों में कभी आम लोगों की आवाजाही मुश्किल थी, जहां सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का पहुंचना एक बड़ी चुनौती रहा, वहां अब बदलाव दिख रहा है। नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ भी इसी बदलाव की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण दुनिया की नजरों से दूर रहा अबूझमाड़ अब अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से लोगों को आकर्षित कर रहा है। गारपा जलप्रपात का साफ पानी, पहाड़ों से उतरती फलधारा, प्राकृतिक कुंड और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह को खास बनाती है।कभी नक्सलवाद के प्रभाव और सुरक्षा संबंधी प्रतिबंधों के कारण बाहरी दुनिया से काफी हद तक कटा रहा यह इलाका अब अपनी प्राकृतिक संपदा, खूबसूरत



पहाड़ियों, जंगलों और जलस्रोतों के कारण लोगों का ध्यान खींच रहा है।

ग्राम गारपा के पास मौजूद एक मनमोहक जलप्रपात इन दिनों चर्चा में है, जो अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर के साथ-साथ प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। नारायणपुर जिले के कच्चापाल जलप्रपात के बाद अब गारपा के पास मौजूद यह छोटा-सा झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर ग्राम गारपा में बीएसएफ

कैंप के पीछे मौजूद एक छोटा-सा जलप्रपात इन दिनों स्थानीय युवाओं और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

कैंप के किनारे से होकर यहां तक पहुंचा जा सकता है और कैंप से करीब 200 मीटर की दूरी पर यह खूबसूरत प्राकृतिक स्थल दिखाई देता है। आकार में भले ही यह जलप्रपात बहुत बड़ा न हो, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता और आसपास का शांत वातावरण इसे खास बना देता है। इन दिनों स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब साझा किए जा रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा और कंटेंट क्रिएटर यहां पहुंचकर इस प्राकृतिक नजारे को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं।

घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बहती जलधारा जब चट्टानों से उतरकर नीचे बने प्राकृतिक कुंड में पहुंचती है, तो यहां

छत्तीसगढ़

भीतर रैनी रस्म के बाद विशाल रथ की चोरी, हजारों लोगों के सामने माड़िया समुदाय ले गए रथ

बस्तर दशहरा में भीतर रैनी रस्म के बाद विशाल रथ की चोरी की गई. माड़िया समुदाय इस परंपरा को निभाता है.

बस्तर। बस्तर में 75 दिनों तक मनाये जाने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है, बल्कि बस्तर की आराध्य दंतेश्वरी देवी के छत्र को आठ चक्रों के विशालकाय विजय रथ में सवारकर परिक्रमा करवाई जाती है। इस रस्म को 21 अक्टूबर बुधवार की देर शाम विधि विधान



के साथ निभाई गई। इस रस्म को देखने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही अन्य राज्यों और विदेशी नागरिकों

को मौजूदगी रही। विजय रथ परिक्रमा हो बस्तर दशहरें में मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है।

बस्तर राज परिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव का कहना है कि बस्तर को भारत देश में मनाया जाने वाले दशहरा पर्व से बस्तर दशहरा काफी अलग

बनाती है। बस्तर में विजय दशमी के दिन भीतर रैनी की रस्म अदायगी की जाती है। इस साल विजय दशमी बस्तर दशहरे में 21

अक्टूबर को मनाया गया। इस रस्म से यह आशय है कि महाराजा आज के दिन सुकह परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं।

महाराजा राजमहल के भीतर बैठकर बस्तरबासियों को दर्शन दिया करते हैं। क्योंकि सदियों पुरानी यह परम्परा रही है कि आम जनता महाराजा का पैर छूते हैं। आशीर्वाद लेकर नजराना पेश करते हैं। इसके बाद देर रात 8 चक्रों के दो मंजिला रथ में बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी के छत्र को रथारुढ़ कर शहर में परिक्रमा करवाई जाती

है-कमलचंद भंजदेव, राजपरिवार सदस्य इस रस्म की अदायगी के बाद देर रात रथ चोरी की रस्म निभाई जाती है। माड़िया समुदाय के लोग 8 चक्रों के विशालकाय रथ को हजारों आंखों के सामने चोरी करके लालबाग स्थित कुम्हड़ाकोट पहुंचाते हैं। इसके बाद अगले दिन बाहर रैनी रस्म के दौरान राजपरिवार राजशाही अंदाज में कुम्हड़ाकोट पहुंचकर माड़िया समुदाय के लोगों के साथ नयाखानी का त्यौहार मनाते हैं। जिसके बाद शान से रथ को वापस राजमहल लेकर पहुंचते हैं।

सुकमा वनमंडल में 6 वन अपराध मामलों में 8 लाख के सागौन जळ

सुकमा। जिले के वन संपदा की अवैध कटाई, संग्रहण और परिवहन के खिलाफ वन विभाग ने सुकमा वनमंडल में अक्टूबर महीने में अब तक 6 वन अपराध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान लगभग 8 लाख रुपए कीमत की सागौन लकड़ी, फर्नीचर और अन्य लकड़ी सामग्री जब्त की गई है। अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 02 ट्रैक्टर और 02 ऑटो रिक्शा भी जब्त किए गए हैं। खास बात यह है कि 21 अक्टूबर की रात में एक ट्रैक्टर में रेत के नीचे लकड़ी छिपाकर ले जाने का मामला सामने आया। वन विभाग ने संबंधित मामलों में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

उपवनमंडलाधिकारी परख सारड़ा ने बताया कि उडुन्दस्ता दल, सुकमा वन परिक्षेत्र कार्यालय और गोलापल्ली वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग-अलग



अलग स्थानों पर कार्रवाई की। वन विभाग के अनुसार अब तक करीब 4.724 घनमीटर सागौन चिरान, सागौन से बने फर्नीचर और अन्य लकड़ी सामग्री जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान दूरकापारा (नीलावरम) निवासी मंगल राम मरकाम और कवासी हड़मा के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया। इनके मामले में ऑटो रिक्शा सहित 10 नग सागौन चि जब्त किए गए वहीं, चिचोरगुड़ा (नीलावरम) सागौन चिरान जब्त किए गए। वहीं, चिचोरगुड़ा (नीलावरम) निवासी दूधी छोटु/गंगा के मामले में 54 नग सागौन चिरान जब्त किए गए। सुकमा के पटनमपारा निवासी खरीम के यहां से 0.668 घनमीटर सागौन से बनी फर्नीचर सामग्री जब्त की गई।

बस्तर दशहरा देखने डेनमार्क से भी पहुंचे विदेशी पर्यटक, बस्तर की संस्कृति आई पसंद

बस्तर। अपनी अनूठी परंपराओं, आदिवासी संस्कृति और 75 दिनों तक चलने वाले विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरे की ओर विदेशी पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने के लिए डेनमार्क से 4 पर्यटकों का दल बस्तर पहुंचा है। डेनमार्क से आए विदेशी पर्यटकों ने कहा कि पहली बार वे छत्तीसगढ़ के बस्तर में आए हैं। इसीलिए वे काफी उत्सुक हैं। बस्तर के लोग काफी अच्छे हैं। बस्तर काफी पसंद आया है। खासकर बस्तर दशहरे को काफी एंजाय कर रहे हैं। बस्तर के ग्रामीण इलाकों और आदिवासी समुदाय के लोग काफी आकर्षक हैं। भले ही भाषा अलग होने के कारण विदेशी पर्यटकों की बातचीत ग्रामीण लोगों को कम समझ आ रही हो, लेकिन उनके चेहरे के भाव और कल्चर से बहुत कुछ समझ आ रहा है। पर्यटक उलरिक का कहना है कि वे लोगों के हाव-भाव और इशारों से भी समझ रहे हैं। वहीं कठिन चीजों को समझने में स्थानीय नागरिक उनकी सहायता गाइड के रूप में कर रहे हैं। 4 सदस्यों की टीम 16 दिनों के लिए भारत आई है। इस दौरान प्रमुख रूप से बस्तर दशहरा को देखा जा रहा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य ओडिशा के कल्चर और नैसर्गिक सौंदर्य को भी आगे देखने का प्लान है।



विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरे की ओर विदेशी पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने के लिए डेनमार्क से 4 पर्यटकों का दल बस्तर पहुंचा है। डेनमार्क से आए विदेशी पर्यटकों ने कहा कि पहली बार वे छत्तीसगढ़ के बस्तर में आए हैं। इसीलिए वे काफी उत्सुक हैं। बस्तर के लोग काफी अच्छे हैं। बस्तर काफी पसंद आया है। खासकर बस्तर दशहरे को काफी एंजाय कर रहे हैं। बस्तर के ग्रामीण इलाकों और आदिवासी समुदाय के लोग काफी आकर्षक हैं। भले ही भाषा अलग होने के कारण विदेशी पर्यटकों की बातचीत ग्रामीण लोगों को कम समझ आ रही हो, लेकिन उनके चेहरे के भाव और कल्चर से बहुत कुछ समझ आ रहा है। पर्यटक उलरिक का कहना है कि वे लोगों के हाव-भाव और इशारों से भी समझ रहे हैं। वहीं कठिन चीजों को समझने में स्थानीय नागरिक उनकी सहायता गाइड के रूप में कर रहे हैं। 4 सदस्यों की टीम 16 दिनों के लिए भारत आई है। इस दौरान प्रमुख रूप से बस्तर दशहरा को देखा जा रहा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य ओडिशा के कल्चर और नैसर्गिक सौंदर्य को भी आगे देखने का प्लान है।

द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का प्रथम दिवस संपन्न

एमसीबी। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को गति देने के लिए जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती नम्रता डोगरे की अध्यक्षता में 22 एवं 23 अक्टूबर 2026 को आयोजित इस प्रशिक्षण के प्रथम दिवस पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों को जनगणना की विभिन्न प्रक्रियाओं, गणना ब्लॉकों के गठन, पर्यवेक्षक सर्वेले के निर्धारण तथा आंकड़ों के व्यवस्थित संकलन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जनगणना कार्य निदेशालय, रायपुर से आए मास्टर ट्रेनर नसीब अहमद खान, सा.अ. ग्रेड-2 तथा जिला नोडल अधिकारी अतुल बंसोड़, सा.अ. ग्रेड-2 ने अधिकारियों को जनगणना कार्य की योजना तैयार करने, कार्मिकों की जिम्मेदारियां निर्धारित करने और पूरी प्रक्रिया को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के संबंध में प्रशिक्षण दिया।

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद गौतम राजवाड़े को दी श्रद्धांजलि

अम्बिकापुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लटोरी में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वीर शहीद गौतम राजवाड़े की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, पुलिस विभाग, विद्यालय परिवार, शहीद के परिजनों एवं ग्रामीणों ने शहीद को नमन कर उनके बलिदान को याद किया। शहीद गौतम राजवाड़े का जन्म 4 फरवरी 1991 को हुआ था। वे सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम तराजू के निवासी थे। विद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष कार्य बल में बस्तर संभाग के जगदलपुर में पदस्थ थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवा देते हुए 19 फरवरी 2015 को नक्सली मुठभेड़ में उन्होंने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। कार्यक्रम में जप सदस्य श्रीमती रजनी पैकरा, पूर्व एसएमसी अध्यक्ष जगरोपन यादव, वर्तमान एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती आरती साहू, थाना लखनपुर के सहायक उपनिरीक्षक मनीष तिवारी, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह तथा अन्य शामिल रहे।

एकादशी वाले दिन रावण दहन, ग्रामीण निकालते हैं झांकी

नारायणपुर। नारायणपुर जिले में दशहरे की परंपरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति, सामूहिक एकता और पीढ़ियों से चली आ रही कलात्मक विरासत को सहेने का भी माध्यम है। विजयादशमी के अगले दिन एकादशी को ग्राम बिजली में आयोजित होने वाला बिजली दशहरा महोत्सव इसी अनूठी परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। बिजली गांव के दशहरा में कबाड़ से जुगाड़ कर तैयार की गई आदमकद राक्षसों की आकर्षक झांकियां, स्थानीय कलाकारों की मनमोहक रामलीला और करीब 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हजारों लोगों के आकर्षण का



एकादशी को ग्राम बिजली में इस महोत्सव का आयोजन होता है। पीढ़ियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी उत्साह और सामूहिक सहभागिता के साथ आगे

केंद्र बना। इस वर्ष भी लगभग पांच हजार ग्रामीणों और दर्शकों की मौजूदगी में आयोजित महोत्सव ने एक बार फिर साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीणों की मेहनत, कल्पनाशीलता और आपसी सहयोग किसी भी आयोजन को विशेष पहचान दिला सकते हैं। नारायणपुर जिले के ग्राम बिजली में दशहरा महोत्सव का आयोजन वर्षों से एक विशेष परंपरा के तहत किया जाता रहा है।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का छत्तीसगढ़ आगमन पर हुआ आत्मीय स्वागत

रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंची। राज्यपाल श्री रमन डेका ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भी उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय से राजस्थान विस अध्यक्ष देवनानी ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से गुरुवार



को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने श्री देवनानी का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर इंदौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद शंकर लालवानी और अमित चिमनानी उपस्थित थे।

सिद्धबाबा गेट रेलवे समपार फाटक 26 से 28 अक्टूबर तक रहेगार बंद

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल



मंडल अंतर्गत भाटापारा एवं हथबंद रेलवे स्टेशनों के मध्य स्थित रेलवे समपार फाटक क्रमांक 385 (कि.मी. 766/13-15) जिसे सिद्धबाबा गेट के नाम से जाना जाता है, पर अप लाइन में अत्यावश्यक मरम्मत कार्य किया जाना है इस कार्य के कारण उक्त समपार फाटक पर 26 सुबह 9 बजे से 28 अक्टूबर 18 बजे तक सड़क यातायात का आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा।

अशोक कुमार गुप्ता ने एनआईटी रायपुर के कुलसचिव का कार्यभार संभाला

रायपुर। अशोक कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय



प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर के कुलसचिव (रजिस्ट्रार) के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में पदस्थ हुए हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात श्री गुप्ता कुलसचिव कार्यालय का नेतृत्व करेंगे तथा इस पद से जुड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। उनकी नियुक्ति संस्थान के प्रशासनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्री गुप्ता को शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव प्राप्त है। एनआईटी रायपुर में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे दिसंबर 2017 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई में अपर कुलसचिव एवं उप कुलसचिव के पद पर कार्यरत रहे। इससे पूर्व, उन्होंने जुलाई 2010 से जून 2017 तक भारतीय खनि विद्यापीठ (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद में सहायक कुलसचिव के रूप में अपनी सेवाएं दीं। वहीं, नवंबर 2004 से जून 2010 तक उन्होंने भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान में सीएलए के पद पर कार्य किया। इन संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने संस्थागत प्रशासन एवं शैक्षणिक शासन-व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक अनुभव अर्जित किया है।

महाराष्ट्र मंडल में रंगते हुए बच्चों की लैड 24 को

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल में शुक्रवार, 23



अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं तीन दिवसीय मराठी सोहळा (मराठी मेला) में विविध आयोजनों की श्रृंखला में सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र नगर स्तरीय छह माह से 15 माह तक के रंगते वाले बच्चों की दौड़ होगी। चौबे कॉलोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल भवन में 24 दिसंबर को दोपहर 3 बजे इस प्रतियोगिता के लिए लोगों में जितनी जिज्ञासा है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह भी। तभी तो इसमें शामिल होने के लिए नौनिहालों के अभिभावक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। महाराष्ट्र मंडल की उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल ने बताया कि रंगते हुए बच्चों की नगर स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है। वहीं इसमें उपहार का आकर्षण निश्चित ही बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी लुभाएगा। विजेता, उपविजेता, सांत्वना पुरस्कार के अलावा विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे, इन्में हेल्दी बेबी, एक्टिव बेबी और बेस्ट ड्रेस्ड बेबी के फ़ाइज़ शामिल हैं। कुल मिलाकर क्राउलिंग बेबी रेस कॉन्टेस्ट के लिए अभी से नौनिहालों के अभिभावकों सहित लोगों में भी काफी उत्सुकता और जोश है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

माता साहिब हासी देवी की जयंती पर 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी

रायपुर। पूज्य माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती के अवसर पर राजधानी में विशेष समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर उनके सम्मान में 200 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया। सिंधी सनातनी समुदाय की आध्यात्मिक संत माता हासी देवी ने अपना जीवन भक्ति, शिक्षा, समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया था। वह शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश्वर थीं।

पूज्य माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर 200 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम उनके जीवन और योगदान को सम्मानित करने से जुड़ा है। माता हासी देवी ने शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश्वर के रूप में धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया। शिक्षा, भक्ति, लंगर, समाज सेवा और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े उनके कार्य आज भी

उनकी विरासत का हिस्सा हैं। रायपुर में आयोजित होने वाला यह समारोह माता साहिब हासी देवी के जीवन, सिंधी समाज की धार्मिक परंपरा और मानव सेवा के लिए उनके योगदान को याद करने का अवसर होगा।

शदाणी दरबार के सचिव उदय साई के अनुसार माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर जारी होने वाला स्मारक सिक्का 35 ग्राम वजन का होगा। शदाणी दरबार के सचिव उदय साई के अनुसार, इसका निर्माण कोलकाता टकसाल में किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस विशेष सिक्के के 550 नग तैयार कराए हैं। विमोचन के बाद श्रद्धालु और सिक्का संग्राहक शदाणी दरबार की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से इसकी बुकिंग कर सकेंगे।

सिक्के में चार धातुओं का इस्तेमाल किया गया है- 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल, 5 प्रतिशत जस्ता।



शदाणी दरबार के सचिव उदय साई ने कहा कि माता साहिब हासी देवी के सम्मान में भारत सरकार द्वारा स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाना पूरे सिंधी समाज के लिए गौरव की बात है। वहीं, संत युधिष्ठिर लाल ने कहा कि स्मारक सिक्के देश की महान विभूतियों की स्मृति को संजोने का माध्यम हैं। ये केवल मुद्रा नहीं, बल्कि देश के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और आने

वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी हैं।

शदाणी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल के अनुसार माता हासी देवी ने अपना जीवन आध्यात्मिक साधना के साथ समाज कल्याण के कार्यों में लगाया।

वह गुरु गद्दी पर विराजमान होने के बावजूद विनम्र रहती थीं और मंदिर तथा वहां आने वाले भक्तों की व्यक्तिगत रूप से सेवा करती थीं। उनके जन्मदिवस समारोह के कार्यक्रम 15 से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाने का भी उल्लेख है।

माता हासी देवी के जीवन से जुड़ी एक मान्यता अकाल के समय शदाणी दरबार के

खाद्य भंडार से संबंधित है। श्रद्धालुओं के अनुसार, अकाल के दौरान उनके आशीर्वाद से दरबार का खाद्य भंडार कभी समाप्त नहीं हुआ। माता हासी देवी ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से कई संतों को भी प्रेरित किया। शदाणी दरबार के संत 'मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है' के आदर्श का पालन करते हैं। दरबार में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संगीत, सांस्कृतिक मूल्यों और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। यहां नियमित रूप से भजन-कीर्तन, भंडारा, तीर्थयात्रा, धार्मिक त्योहार और संत सभाओं का आयोजन होता है।

इन गतिविधियों के माध्यम से धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। हरिद्वार में भारत माता मंदिर के सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित पवित्र गंगा घाट और वहां स्थापित पूज्य माता साहिब हासी देवी की प्रतिमा भी उनकी स्मृति से जुड़ी हुई है।

सिरपुर हमारी समृद्ध सभ्यता, कला और ज्ञान परंपरा की अनमोल धरोहर : साय

■ यूनेस्को की संभावित सूची में सिरपुर का शामिल होना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिरपुर को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। साय ने कहा कि सिरपुर हमारी समृद्ध सभ्यता, कला, आध्यात्मिकता और ज्ञान परंपरा की अनमोल धरोहर है। प्राचीन काल से ही सिरपुर शिक्षा, संस्कृति, धर्म और स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत छत्तीसगढ़ के गौरवशाली

अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की जीवंत पहचान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व विरासत भी, विकास भी के संकल्प के साथ देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पर्यटन की नई संभावनाओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। साय

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने के साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सिरपुर सहित छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी गौरवशाली विरासत से परिचित हों और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की कीर्ति विश्वभर में और अधिक विस्तारित हो।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर सियासी घमासान

मुरिया दरबार में शामिल होने को लेकर कांग्रेस-भाजपा के बीच जुबानी जंग

जगदलपुर। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर आई हैं इस दौरान को लेकर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राष्ट्रपति के दौरे को फिजूल खर्च बताया है,जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दौरे को लेकर कहा कि राष्ट्रपति जी तो दत्तेवाड़ा भी आए थे, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ बस्तर की जनता को? कुछ नहीं हुआ। 6 करोड़ 50 लाख बस्तर पंडुम का बिल हमारे बस्तर की जनता की गाढ़ी कमाई से भरे हैं। कोई फायदा नहीं हुआ बस्तर को। दीपक बैज ने कहा राष्ट्रपति को सिर्फ एक मुखौटा बनाकर लाया जा रहा है ताकि फिर से बस्तर पंडुम जैसे राष्ट्रपति के नाम से करोड़ों का टेंडर



लगा लें। करोड़ों का टेंट लगा दें और घोटाला कर लें। राष्ट्रपति को सिर्फ मुखौटा बनाकर यहाँ घोटाला कराने के लिए ला रहे हैं। राष्ट्रपति जी आए वेलकम हैं, लेकिन उनके आने से बस्तर को कोई फायदा नहीं होना है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कांग्रेस पार्टी की यह पुरानी आदत रही

है कि वह देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठें महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करे।

केदार कश्यप ने कहा बस्तर दशहरा का यह पर्व सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। मुरिया दरबार के माध्यम से हम कैसे अपने गांवों और क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय करते हैं। कांग्रेस ने इसे समझने की कोशिश ही नहीं की।

यह हम सभी बस्तरवासियों के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रपति जी पहली बार हमारे ऐतिहासिक मुरिया दरबार में शिरकत करने आ रही हैं। मुरिया दरबार की परंपरा कोई आज की नहीं, बल्कि लगभग 500 से 600 साल पुरानी है।

ग्राम बगौद, जिला बेमेतरा में ‘खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ

■ आईसीएअर एंड एनआईवीएसएम एवं कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा के समन्वय से आयोजित कार्यक्रम; फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पर जोर

रायपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्द्वारा राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा के समन्वय से आज ग्राम बगौद, जिला बेमेतरा, में ‘खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य किसानों को फसलों में कीटों, रोगों एवं अन्य जैविक तनावों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तथा वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को खेत स्तर तक पहुंचाना है।

कार्यक्रम में ICAR&NIBSM के संयुक्त निदेशक एवं अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. पंकज शर्मा, डॉ. एस. के. जैन, डॉ. के. सी. शर्मा, डॉ. अजय वर्मा तथा कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा के डॉ. लव कुमार उपस्थित रहे। वैज्ञानिकों ने किसानों से संवाद कर उनकी कृषि संबंधी समस्याओं पर चर्चा की और फसल सुरक्षा के व्यावहारिक उपाय बताए।

इस अवसर पर डॉ. पंकज शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि खेत बचाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य फसलों को जैविक तनावों से सुरक्षित रखने के साथ-साथ कृषि को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल बनाना है। उन्होंने किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने, उपयुक्त वैकल्पिक फसलों को शामिल



करने, फसल चक्र अपनाने तथा कीटों एवं रोगों की समय पर पहचान कर समन्वित प्रबंधन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विविधीकृत फसल प्रणाली से कृषि जोखिम कम करने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

डॉ. के. सी. शर्मा ने फसलों में कीट एवं रोगों की समय पर पहचान, समन्वित कीट प्रबंधन, संतुलित पोषण तथा रासायनिक कीटनाशकों एवं रोगनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को पर्यावरण-अनुकूल एवं वैज्ञानिक फसल सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया।

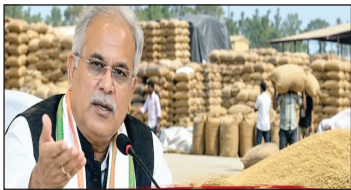
डॉ. लव कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा ने स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप फसल विविधीकरण, फसल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा वैज्ञानिक कृषि सलाह के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को उपलब्ध कृषि तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन एवं लाभप्रदता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

धान खरीदी पर सियासत : भूषेश बघेल ने सरकार को घेरा, पूछा-

आखिर 1 नवंबर से क्यों नहीं हो रही है शुरुआत

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूषेश बघेल ने धान खरीदी के मुद्दे पर कहा कि सरकार धान खरीदी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उन्होंने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने की वकालत करते हुए सवाल किया कि क्या सरकार समय पर धान नहीं खरीदना चाहती? सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री भूषेश बघेल दशहरा के बाद पहली बार मीडिया से रु-ब-रु ह हुए। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा कि जीरो टोरलेन्स की दावे वाली सरकार में गड़बड़ी हुई है। इस मामले की जाँच क्यों नहीं हो रही है? सरकार में बैठे लोग परीक्षा पास करवा रहे हैं। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका देनी चाहिए। अब तक पीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होना भी सवालों के घेरे में है। 2024 पीएससी के अभिभावकों सहित लोगों में भी काफी उत्सुकता और जोश है।



भूषेश बघेल ने रायपुर के लोगों को ट्रैफिक के नाम प्रताड़ित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजधानी में मंत्री और अधिकारी दो-दो बंगले रह रहे हुए हैं। सभी मंत्रियों को राजधानी का बंगला छोड़ देना चाहिए। बीटीआई ग्राउंड में व्यवसायिक कॉलेक्स बनाना बेहद ही गलत है। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूषेश बघेल ने इससे साथ महतारी वंदन के हितग्राहियों से वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि महतारी वंदन में हितग्राहियों की संख्या 70 लाख से घटकर 68 लाख हुई, जबकि पात्र हितग्राहियों की संख्या बढ़नी चाहिए।

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर मामले की श्रेणी राजस्व ईशतहार

संर्भर्:- जिला- रायपुर -अभनपुर प.ह.नं. 00022 सारखी ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक- RD202627441631000006 तहसील-अभनपुर प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम सारखी के वर्तमान भूमिसूची पदमनाथ ओझा पिता/पति-स्व. मंगलदास ओझा पता-वाई न.53 यु.गुल्लक 'प्लास्टिक फैक्ट्री' संतोषी नगर रायपुर छ.ग. के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 565/17(0.1900), 619/5(0.0200) में प्रस्तावित भूमिसूचि/केला प्रशान्त ओझा पिता/पति-पदमनाथ ओझा पता-संतोषी नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छडमो नाम पर पंजीयन/पंती होने के उपरान्त नामांतरण / अभिलेख दुरुस्ती / खाता विभाजन लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरताओं के न्यायालय में पंजी विचारधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02/11/2026 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय तहसीलदार अभनपुर पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपति हो तो इशतहार प्रकाशन उपरान्त प्रकरण की आपापी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपति स्वयं / अधिका / आममुख्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त दावा आपति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदसुदा से आज दिनांक 09/10/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार, सीता शुक्ला तहसील - अभनपुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव (आदिवासी विकास शाखा)

क्रमांक/2938/आ.वि./निर्माण / 2026-27 कोण्डागांव, दिनांक 19/10/2026

ई-प्रोक्चरमेंट (तृतीय) निविदा आमंत्रण सूचना			
एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभागीय छात्रावास / आश्रम भवनों में मरम्मत / अनुरक्षण/जीर्णोद्धार / लघु निर्माण/निर्माण कार्य हेतु विकासखंडवार वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर पर जोनल निविदा आमंत्रित की जाती है:-			
ई-टेंडरिंग हेतु निर्धारित विधि निम्नानुसार होगी-			
1- निविदा प्रारंभ तिथि	19.10.2026		
2-अंतिमाला निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	26.10.2026 अपरान्ह 5.00 बजे तक		
3-निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि (स्पीड पोस्ट से)	30.10.2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक		
4- निविदा खोलने की तिथि	03.11.2026 पूर्वान्ह 3.00 बजे से		
5-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रुपये 3000/-		
6-कार्य पूर्णता की अवधि (प्रति कार्य)	कार्य अनुसार		
7-ठेकेदार की श्रेणी	द वर्ग या अधिक		
क्रमांक	कार्य का नाम	वार्षिक कार्यों की अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि (रु.में)
01	02	03	04
01	जोनल निविदा विकासखंड केशकाल अंतर्गत सेक्टर क्रमांक 01	60.00	45,000.00
02	जोनल निविदा विकासखंड केशकाल अंतर्गत सेक्टर क्रमांक 02	60.00	45,000.00

टिप्प:- 01. आदिवासी विकास विभाग कोण्डागांव अंतर्गत पूर्व में जारी कार्यादेश के ऐसे ठेकेदार जिन्होंने निर्माण/लघु निर्माण/अनुरक्षण/जीर्णोद्धार कार्य को निर्धारित अवधि समाप्त होने के 03 माह तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया है वे इस निविदा हेतु अपात्र होंगे। 02. उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा को सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्चरमेंट वेबसाइट -https://eproc.cgstate.gov.in में देखी जा सकती है। 03 धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ही कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोण्डागांव

जी-262704117/6

अमित शाह : सख्ती के साथ संयम का मेल

हरिश गुप्ता

कुछ सप्ताह पहले राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूँज रहा था—अमित शाह कहाँ हैं ? केंद्रीय गृह मंत्री की राजनीतिक सक्रियता मानो अचानक थम—सी गई थी। 20 जुलाई को जंतर–मंतर पर उमड़ी भीड़ और संसद की ओर मार्च के दौरान हुए हंगामे ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस को छवि को नुकसान पहुंचाया था। यदि अमित शाह पदों के पीछे से राजनीतिक समीकरण साधने में व्यस्त थे तो उनके करीबी दायरे के बाहर बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। लेकिन अब अचानक तस्वीर बदल गई है। 10 अक्तूबर को जब सीजेपी के प्रदर्शनकारी दूसरी बार राजधानी लौटे तो अमित शाह ने अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था— किसी भी कीमत पर किसी को जंतर–मंतर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सख्ती के साथ नरमी का उनका अंदाज सबके सामने था। इस बीच शाह दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वे केवल नियमित सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में अपनी जगह लगातार मजबूत कर रहे हैं। उनकी धमाकेदार वापसी पिछले महीने महाराष्ट्र के दो दिवसीय ठहर से हुई। इसके बाद 17 सितंबर को वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन समारोह में उनकी मौजूदगी ने भी राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा। उनका राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के विज्ञापन भी काफी कुछ बयां कर रहे थे। कुछ तस्वीरों में शाह नई खुली सड़क पर चलते हुए, लोगों की ओर हाथ हिलाते हुए और उस पल का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। इसके बाद नोएडा की बारी आई। शाह ने उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। यह घटनाक्रम इसलिए खास था, क्योंकि शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच कथित दूरी तथा आपसी मतभेदों की अटकलें लगाई जा रही थीं। 30 सितंबर को शाह एक बड़ी भाजपा रैली के लिए जालंधर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मेघालय, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और बाद में पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों का दौरा किया। कुछ समय के अंतराल के बाद वे एक बार फिर पश्चिम बंगाल से पंजाब तक लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। 17 सितंबर के अंदरूनी सड़क का कहनाई है कि यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है और उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त है। यदि सत्तारूढ़ खेमे तक पहुंच रही सूचनाओं पर भरोसा किया जाए, तो अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के लिए तस्वीर मिली–जुली है। पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षणों, चुनावी आकलन करने वालों और अन्य स्रोतों से मिले संकेतों के अनुसार, भाजपा उत्तरप्रदेश, मणिपुर और गोवा में अपनी स्थिति को लेकर सहज है। लेकिन उत्तराखंड में उसे कई कारणों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दुय्यंत गौतम को राज्यपाल नियुक्त किया जाना भी शामिल है। पंजाब में यदि भाजपा अकेले चुनाव लड़ती है तो उसकी स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है। पंजाब से मिले विभिन्न स्रोतों के फीडबैक के बाद ही भाजपा अब शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के साथ हाथ मिलाने के विकल्प पर विचार कर रही है। ऐसी खबरें भी हैं कि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर जल्द ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में लौट सकती हैं और मोदी मंत्रिमंडल में उनकी वापसी हो सकती है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

20-सर्वास्तितवाद (वैभाषिक)

गताक्त से आगे...

वसुबन्धु का महान् ग्रन्थ अधिधर्मकोश जो कि आधुनिक समय में न केवल सर्वास्तितवाद और वैभाषिक के विषय में, प्रत्युत अन्य बौद्ध सम्प्रदायों के विषय में हमारे परिचय का मुख्य स्रोत है, इसी ज्ञानप्रस्थानशस्त्र पर निर्भर था। अधिधर्मकोश पर वसुबन्धु ने स्वयं भी अपनी टीका लिखी थी और दूसरी टीका यशोमित्र की लिखी है, जिसका कुछ अंश श्वेरबात्सकी द्वारा सम्पादित होकर लेनिन–पेड से प्रकाशित हो चुका है। अधिधर्मकोश का डी० ला० वाली प्रूस्नि ने फ़्रञ्च भाषा में अनुवाद किया है। यह ग्रन्थ जो किसी समय भारत के कोने कोने में पढ़ा जाता था, दुर्भाग्य से आज मूल संस्कृत रूप में विद्यमान नहीं है। केवल उसके चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद मिलते हैं। जिनके सहारे प्रूस्नि ने फ़ेश्च अनुवाद किया है, परन्तु उस अनुवाद के साथ साथ ही उस प्रतिभाशाली अनुवादक ने जगह जगह

टीकाओं के सहारे संस्कृत के मूलरूप को भी पुनरुज्जीवित किया है। उसी के आधार पर श्री राहुल सांकृत्यायन ने बनारस से अधिधर्मकोश की संस्कृत रूपरेखा प्रकाशित की है। एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जिसमें अधिधर्मकोश के सार को गागर में सागर के समान भर दिया है, श्वेरबात्सकी का 'Central Conception of Buddhism' नामक ग्रन्थ है।

मुख्य सिद्धान्त— सर्वास्तितवाद के मुख्य सिद्धान्त क्या थे ? विशेष कर प्रश्न यह है कि उनका थेरावाद या प्राचीन बौद्ध सिद्धान्तों से क्या अन्तर था, जिससे उनका नाम सर्वास्तितवाद पड़ा। वैदिक सम्प्रदाय के दार्शनिक लेखक, कम से कम पिछले युग में, ऐसा समझते थे कि सर्वास्तितवाद नाम विज्ञानवाद और शून्यवाद की अपेक्षा से पड़ा, अर्थात् पिछले पदार्थों सम्प्रदाय बाह्य पदार्थों का (भूत और भौतिक पदार्थों का) अस्तित्व नहीं मानते और सर्वास्तितवादी मानते थे।

कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित किचूर रियासत अपनी शांति और समृद्धि के लिए जानी जाती थी। इसी के केंद्र में एक अदृट संकल्प की महिला थीं, जिनका नाम रानी चेन्नम्मा था। किचूर की रानी चेन्नम्मा ने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता के पहले शोले को प्रज्वलित किया था। आज ही के दिन यानी की 23 अक्तूबर को रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था। बता दें कि रानी चेन्नम्मा भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानी चेन्नम्मा ने 19वीं सदी में पहला सशस्त्र विद्रोह किया।

बेलगामों के काकती गांव में 23 अक्तूबक 1778 को रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था। उन्होंने बचपन से तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी का गहन प्रशिक्षण

क्रमशः...

सक्रियता भी निर्णायक हो सकती है।

तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में कोलकाता नगर निगम की राजनीति में सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी के बाद फिरहाद हकीम प्रमुख चेहरा बने। 2018 में शोभन चटर्जी के पद छोड़ने के बाद फिरहाद हकीम ने मेयर की जिम्मेदारी संभाली। 2021 के चुनाव के बाद भी वह मेयर बने रहे।

लेकिन 2026 में राज्य की सत्ता में बदलाव के बाद नगर निगम की राजनीति भी बदल गई। मुख्यमंत्री सुचेंदु अधिकारी ने जून में घोषणा की कि कोलकाता नगर निगम का चुनाव दिसंबर 2026 तक कराया जाएगा। इसके बाद निगम के निर्वाचित बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त किए जाने से चुनाव की राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई।

अब तृणमूल कांग्रेस के सामने यह साबित करने की चुनौती है कि नगर निगम में उसका जनाधार केवल राज्य की सत्ता के कारण नहीं था। दूसरी ओर, भाजपा के लिए यह अपने शासन को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समर्थन में बदलने का अवसर है।

इस चुनाव का सबसे बड़ा बदलाव परिसीमन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अगस्त 2026 में संशोधन विधेयक पारित कर कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का रास्ता साफ किया। सितंबर में राज्य सरकार ने संशोधित वार्डों की व्यवस्था से संबंधित अधिसूचना जारी की। निगम के 16 बोरो पहले की तरह बने रहेंगे। इसका मतलब है कि अब 65 अतिरिक्त वार्ड होंगे। राजनीतिक दलों को ज्यादा उम्मीदवार उतारने होंगे और कई जगह पुराने वार्डों की सीमाएं बदलने से उम्मीदवारों का पारंपरिक जनाधार भी प्रभावित हो सकता है। सरकार ने इस बदलाव के पीछे आबादी के वितरण में परिवर्तन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने की जरूरत बताई है।

हालाँकि, परिसीमन की प्रक्रिया और वार्डों की सीमाओं को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। इसलिए चुनाव में यह मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है।

ज्ञान/मीमांसा

2029 में मोदी को चुनौती देने के लिए राहुल को बदलनी होगी राजनीति

शेखर गुप्ता

राहुल गांधी इस समय राजनीतिक विरोधियों और समर्थकों के बीच सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं। उनके भविष्य को लेकर होने वाली चर्चाओं में दो दिलचस्प रूझान प्रमुख हैं और दोनों एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। एक ओर यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के बीच ही राहुल गांधी की भविष्य की संभावनाओं को लेकर असहमति हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी और उनके समर्थक इस विषय पर पूरी तरह एकमत हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थक राहुल गांधी को खारिज करते हैं। उनके लिए राहुल ‘पप्पू’ हैं यानी उपहास का पात्र। अक्सर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी यह शेखी बघारते हैं कि राहुल गांधी उनके लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया हमेशा इसके उलट रहा है। उनकी नजर में राहुल गांधी और गांधी परिवार ही एकमात्र संभावित चुनौती हैं।

यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार का केंद्र बार–बार राहुल गांधी बन जाते हैं। यहां तक कि किसी ऐसे राज्य के चुनाव में भी जहां कांग्रेस की कोई खास भूमिका नहीं है, मोदी उन्हें निशाना बनाते हैं। इसी सप्ताह उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के ‘कौंटिल्य’ कहे जाने वाले अमित शाह को भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलने के लिए मैदान में उतारा। भले ही भाजपा का समर्थक वर्ग इन हमलों को हंसी में उड़ा दे लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जानते हैं कि असली चुनौती कौन है। नेता और उसके समर्थक आधार के बीच इस तरह के विरोधाभास बहुत कम देखे गए हैं।

कांग्रेस के मामले में राहुल गांधी और उनके समर्थक एकमत हैं कि सत्ता उनकी मुट्ठी में है बशर्ते चुनाव निष्पक्ष हो। इस विश्वास में यह प्ररोक्ष आरोप भी निहित है कि 2019 से लेकर अब तक भाजपा ने सभी चुनावों में धोधली करके जीत हासिल की है। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करके और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा उनकी एसआईआर प्रक्रिया के गठजोड़ के जरिये। 2014 में लोक सभा में अब तक की सबसे कम 44 सीटें जीतने से लेकर 2019 में 52 और 2024 में 99 सीटें जीतने तक कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार 19 से 21 फीसदी के बीच बना रहा है। यानी हर पांच में से एक भारतीय स्वाभाविक रूप



से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह ‘हाथ’ को वोट देता है। 1996 से 2009 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग 25 फीसदी के आसपास बना रहा। यानी हर चार में से एक मतदाता भाजपा को वोट देता था। यह गठबंधन के दौर का समय था।

मोदी ने 2014 में इस समीकरण को बदल दिया। तब से भाजपा का वोट प्रतिशत 37 से 40 फीसदी के बीच बना हुआ है। अपने पुराने आधार से 12 से 15 फीसदी अंकों की यह बढ़ोतरी बहुदलीय व्यवस्था में असाधारण और विपक्ष के लिए बेहद नुकसानदायक है। यह सोचना सही नहीं होगा कि निकट भविष्य में राहुल गांधी कांग्रेस के वोट प्रतिशत को 37 फीसदी तक पहुंचा देंगे। लेकिन यदि वे अपने मूल वोट आधार में महज 5–6 फीसदी की और वृद्धि कर लेते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। 32 फीसदी वोट के साथ भी भाजपा का दबदबा बना रहेगा लेकिन लोक सभा में उसकी सीटें घटकर 200 के निचले स्तर तक या उससे भी नीचे आ सकती हैं। वह फिर भी सरकार बना सकती है लेकिन तब वह वास्तव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की गठबंधन सरकार होगी जिसके साथ तमाम जटिलताएं भी आएंगी। मोदी और शाह ने इस चुनौती को कभी हल्के में नहीं लिया। वे यह नहीं मानते कि विपक्ष में राहुल गांधी भाजपा के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं। वे जानते हैं कि हर पांच में से एक मतदाता का समर्थन हासिल करने वाली कांग्रेस ही उनकी एकमात्र चुनौती है। और कांग्रेस गांधी परिवार के बिना एकजुट नहीं रह सकती। अहम सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में राहुल गांधी की राजनीति किस दिशा में जाएगी ?

फिलहाल उनका पूरा ध्यान मोदी के खिलाफ सड़कों पर जनांदोलन खड़ा करने पर है। वे किसी के भी साथ साझेदारी करने को तैयार हैं। राहुल को अब तक यह समझ जाना चाहिए था कि भारत में राजनीतिक बदलाव या तो किसी दल के खुद चुनाव जीतने से आता है या फिर दूसरों के साथ

मिलकर मौजूदा सत्ता को हराने से होता है।

जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले नव निर्माण आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस की रेलवे हड़ताल की संयुक्त ताकत भी इंदिरा गांधी की सरकार को नहीं गिरा सकी। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

(आरएसएस), लोहियावादी आंदोलन की सड़क पर उतरने की ताकत और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन भी हासिल था। इसके बावजूद उन्हें 1977 के चुनाव का इंतजार करना पड़ा। इसी तरह 2010 से 2012 के बीच जमीन गंवा चुके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) को अन्ना आंदोलन और आरएसएस/भाजपा ने सत्ता से बाहर नहीं किया। इस सवाल का फैसला करने के लिए 2014 के चुनाव का इंतजार करना पड़ा।

2029 का अगला आम चुनाव राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का अवसर होगा। तब भी वे केवल 59 वर्ष के होंगे जो भारतीय राजनीति के लिहाज से अपेक्षाकृत कम उम्र है। राहुल गांधी को मतदाताओं के सामने एक बेहतर, रचनात्मक और आशावादी राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना होगा। यदि राहुल गांधी चुनाव जीते हैं तो वे मोदी और भाजपा से अलग क्या करेंगे ? में यहां कुछ सवाल रखना चाहता हूं। चुनाव आयोग में सुधार? वे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस तरह करना चाहेंगे और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता कैसे बहाल करेंगे ? कांग्रेस/संप्रग के दौर से तो कोई प्रेरणा नहीं मिलती। उनके दिवंगत पिता ने 1989 में चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय निकाय बनाकर उसे कमजोर करने की कोशिश की थी। वे यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि गैर नागरिक (भाजपा के शब्दों में ‘युसपैटिया’) मतदाता न बन सकें ?

न्यायपालिका, सीबीआई और अन्य प्रमुख एजेंसियां: इनके मामले में भी वे क्या बदलाव करेंगे ? टृप्त जैसी चुनौती से निपटना? वे टृप्त जैसी चुनौती का सामना कैसे करेंगे ? अमेरिका के प्रति उनकी नीति किस तरह अलग होगी ? चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद? चीन से निपटने की क्या योजना है ? पाकिस्तान और उसके समर्थन वाले आतंकवाद के प्रति उनका रवैया मोदी से किस तरह अलग होगा ? वे मोदी से अधिक नरम रख अपनाएंगे या सख्त ? पश्चिम एशिया और इजरायल: इन क्षेत्रों के प्रति उनका दृष्टिकोण मोदी की नीति से किस तरह अलग होगा ? ऊर्जा, पूंजी और सोने की कमी: ऊर्जा, पूंजी और सोने की

लगातार बनी रहने वाली तथा अर्थव्यवस्था को पंगु करने वाली तिहरी कमी से निपटने की उनकी क्या योजना है ? अब इसमें एआई और सॉफ्टवेयर सेवाओं को भी जोड़ सकते हैं। वे भारत को निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र कैसे बनाएंगे ?

रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं: ‘छात्रों की गूँज’ सुनाई दे रही है। लेकिन वे अधिक रोजगार कैसे पैदा करेंगे ? कम पढ़े–लिखे लोगों के लिए क्या वे मनरेगा को फिर से बहाल करेंगे या उसका कोई ‘नया और बेहतर’ संस्करण लाएंगे ? क्या वे मुफ्त अनाज देना जारी रखेंगे ? जाति जनगणना और सामाजिक न्याय: क्या जाति जनगणना अब भी सामाजिक न्याय का माध्यम है ? इसके रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे ? रवंत रेड्डी को समझ नहीं आ रहा कि अपनी जाति जनगणना का क्या करें। क्या राहुल डी.के. शिवकुमार से कम से कम उनके जाति जनगणना के आकड़े जारी करने को कहेंगे ?

शिक्षा व्यवस्था में सुधार: भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी खत्म करने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और युवाओं को रोजगार के अधिक योग्य बनाने के लिए वे शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करना चाहते हैं ? व्यापार और आर्थिक सुधार: वे कहते हैं कि वे व्यापार या पूंजी के विरोधी नहीं हैं। वे केवल एकाधिकार नहीं चाहते और सबको समान अवसर देना चाहते हैं। वे इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे ? आर्थिक सुधारों को लेकर उनकी अवधारणा क्या है ? अल्पसंख्यकों का मुख्यधारा में समावेश: चूँकि वे और उनके ‘धर्मनिरपेक्ष’ सहयोगी शिकायत करते हैं कि अल्पसंख्यकों को हाशिये पर धकेला जा रहा है इसलिए वे उन्हें मुख्यधारा में कैसे शामिल करेंगे ? और अंत में, उनकी टीम में कौन है या कौन–कौन होंगे ?

एक विश्वसनीय चुनौती देने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए राहुल को इन सवालों के जवाब देने होंगे और मतदाताओं के सामने नए विचार रखने होंगे। मोदी ने 2012 के अंत तक ‘अच्छे दिन’ लाने का वादा करना शुरू कर दिया था। 2029 के चुनाव से लगभग इतनी ही दूरी पर खड़े राहुल गांधी आज क्या वादा कर रहे हैं ? राहुल गांधी जो भी रास्ता चुनें वे 2029 के चुनाव में एक बार फिर इस शोर के भरोसे नहीं उतर सकते कि मोदी की लोकप्रियता ‘गिर’ रही है। यह रणनीति पहले ही तीन बार विफल हो चुकी है।

अंग्रेजों को घुटनों पर ले आई थीं रानी चेन्नम्मा



लेना शुरूकर दिया था। फिर किचूर के राजा राजा मल्लसारजा के साथ उनका विवाह हो गया।

बता दें कि रानी चेन्नम्मा का असली पराक्रम तब उजागर हुआ, जब किचूर रियासत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गिड़–दृष्टि पड़ी। उस समय तक अधिकतर भारतीय शासक ब्रिटिश सैनिकों के आगे घुटने टेक चुके थे। लेकिन इसके उलट रानी चेन्नम्मा ने स्वतंत्रता और सम्मान की

राह चुनी। रानी चेन्नम्मा पर दुखों का पहाड़ तब टूटा, जब उनके पति राजा मल्लसारजा और इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। किचूर का सिंहासन खाली हो गया और रियासत पर सेंट्रल के बादल मंडराने लगे।

साल 1824 में अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के तहत किचूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में का ऐलान किया। यह रानी चेन्नम्मा को मंजूर नहीं था। उन्होंने अंग्रेजी सेना से जमकर लोहा लिया और सशस्त्र संघर्ष किया। अपने अपूर्व शौर्य प्रदर्शन के बाद भी रानी चेन्नम्मा अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकीं और अंग्रेजों द्वारा उनको कैद कर लिया गया।

ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया। लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एलफिंस्टन को एक पत्र भेजा। उन्होंने

किचुरु के मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया। लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और किचुरु के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने किचुरु के खजाने और आभूषणों के जखीरे को जब्त करने की कोशिश की जिसका मूल्य करीब 15 लाख रुपये था। लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंग्रेजों ने 20,000 सिहाफियों और 400 बंदूकों के साथ किचुरु पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। अंग्रेजों की कैद में रहते हुए 21 फरवरी 1829 को रानी चेन्नम्मा का निधन हो गया। साल 1977 में रानी चेन्नम्मा द्वारा देश के लिए किए योगदान को याद करते हुए भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। आज भी कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।

कोलकाता ननि: मेयर की कुर्सी पर अब भाजपा की नजर!

सत्येंद्र प्रताप सिंह

पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोलकाता का महत्व हमेशा से रहा है। राज्य की राजधानी होने के साथ–साथ यह शहर राजनीतिक आंदोलनों, सत्ता संघर्ष और विचारधाराओं की लड़ाई का केंद्र भी रहा है। इसलिए कोलकाता नगर निगम का चुनाव केवल पार्षदों के चयन तक सीमित नहीं रहता। इसके नतीजों में शहर के राजनीतिक मिजाज और प्रमुख दलों की संगठनात्मक ताकत की झलक भी मिलती है। हालांकि, नगर निगम और विधानसभा चुनावों के मुद्दे एक जैसे नहीं होते। विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और व्यापक राजनीतिक एजेंडे की भूमिका बड़ी होती है, जबकि निगम चुनाव में वार्ड स्तर के समीकरण, स्थानीय उम्मीदवार, नागरिक सुविधाएं और पार्षदों का काम अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। यही वजह है कि विधानसभा में मजबूत प्रदर्शन करने वाली पार्टी के लिए नगर निगम में जीत अपने आप सुनिश्चित नहीं हो जाती।

इस बार चुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि वार्डों की संख्या में बड़ा बदलाव हुआ है। पुराने 144 वार्डों की जगह अब 209 वार्डों की व्यवस्था की गई है। यानी 65 नए वार्ड जुड़ने से चुनावी नक्शा और उम्मीदवारों के चयन का गणित बदल सकता है। ऐसे में मुकाबला केवल राजनीतिक लोकप्रियता का नहीं, बल्कि नए वार्डों में संगठन और जनाधार स्थापित करने का भी होगा।

कोलकाता नगर निगम की राजनीति में वर्ष 2000 निर्णायक साबित हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने निगम चुनाव जीतकर वामपंथी दलों को चुनौती दी। सुब्रत मुखर्जी मेयर बने। यह ममता बनर्जी के लिए शहरी राजनीति में अपनी ताकत स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर था।

लेकिन तृणमूल कांग्रेस की यह जीत स्थायी नहीं रही। 2005 के चुनाव में वाममोर्चा ने वापसी की और विकास रंजन भट्टाचार्य मेयर बने। इससे साफ हुआ कि कोलकाता में तृणमूल का उभार होने के बावजूद वामपंथ का संगठन और स्थानीय आधार



पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। फिर 2010 में राजनीतिक तस्वीर बदल गई। तृणमूल कांग्रेस ने 141 में से 97 सीटें जीतकर निगम की सत्ता हासिल की। इसके बाद 2011 में विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने वाममोर्चा को सत्ता से बेदखल कर दिया।

2015 के निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 144 में से 114 सीटें जीत लीं। वामपंथ, कांग्रेस और भाजपा के लिए यह बड़ा झटका था। कोलकाता के नगर प्रशासन में तृणमूल की पकड़ और मजबूत हो गई। यह वह दौर था, जब भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विधानसभा चुनावों में बढ़ती चुनौती के बावजूद कोलकाता नगर निगम में तृणमूल को रोकना उसके लिए आसान नहीं था।

2021 के निगम चुनाव ने तृणमूल कांग्रेस के वर्चस्व पर मुहर लगा दी। पार्टी ने 144 में से 134 सीटें जीत लीं। भाजपा को सिर्फ तीन, कांग्रेस को दो और वामपंथी दलों को कुल दो सीटें मिलीं। तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए।

यह नतीजा तृणमूल के पक्ष में बेहद मजबूत था। भाजपा 2021 के विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी थी, लेकिन उसी साल नगर निगम चुनाव में वह उस राजनीतिक ताकत को सीटों में नहीं बदल पाई। यही कोलकाता की राजनीति का महत्वपूर्ण पहलू है। विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को व्यापक समर्थन मिलना और वार्ड स्तर पर स्थानीय चुनाव जीतना दो अलग–अलग बातें हैं। निगम चुनाव में उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, स्थानीय संगठन और नागरिक समस्याओं पर उसकी

आज का इतिहास

1764 मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में पराजित हुआ ।

1850 महिलाओं के अधिकारों को लेकर पहली बार अमेरिका में नेशनल वुमेन राइट कॉन्वोकेशन शुरू हुआ था।

1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी मित्र में ब्रिटिश व जर्मन सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ।

1943 सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिन्द फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की थी।

1946 त्रिग्वेली (नार्वे) सं.रा. संघ के प्रथम महासचिव नियुक्त हुए थे। 1947 गेटी कोरी और उनके पति कार्ल कोरी को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

1956 हंगरी की जनता ने पूर्व सोवियत संघ के वर्चस्व के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया था।

1958 रूसी कवि बोरिस पास्तरनाक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था।

1973 अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन वाटरगेट मामले में टेप जारी करने पर सहमत हुए थे।

1980 लीबिया और सीरिया द्वारा एकीकरण की घोषणा की गयी थी।

1989 हंगरी सोवियत संघ से 33 वर्षों के बाद आजाद होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बना था।

1998 पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या का समाधान आत्म निर्णय से करने की मांग दोहरायी थी।

1998 जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था।

2000 अमेरिकन मंत्री मेडलिन की उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग से मुलाक़ात की थी।

2001 नासा के मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा शुरू की थी।

2001 एप्पल ने आईफॉड बाज़ार में उतारा था।

2003 भारत और बुल्गारिया ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किये थे।

2003 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान ने अपनी परमाणु रिपोर्ट सौंपी थी।

2004 जापान में आघ भूकंप ने 85 हजार लोगों को बेघर कर दिया था।

2006 सूडान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दूत को देश छोड़ने का आदेश दिया था।

2007 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आर.के. राघवन को अपने नये सलाहकारी बोर्ड में नियुक्त किया था।

2008 नया कम्पनी विधेयक लोकसभा में पेश हुआ था।

2011 तुर्की के पूर्वी वान क्षेत्र में आए भूकंप में 264 लोग मारे गए थे।

सीजेपी के विरोध में लाल हिट जनता पार्टी का उदय

सौरभ वार्धोय

देश की राजनीति में विरोध और प्रतिरोध की नई तस्वीर सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अभिजीत दीपके से जुड़ी बताई जा रही कॉंकरोच जनता पार्टी के मुकाबले लाल हिट जनता पार्टी नाम से एक नए संगठन के सामने आने की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में इस संगठन की पहली सदस्यता बैठक आयोजित की गई, जिसमें शामिल लोगों ने सीजेपी, कांग्रेस और अन्य प्रदर्शनकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि लोकतंत्र में विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए और असहमति का जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए।लाल हिट जनता पार्टी’ के प्रमुख और संयोजक अयान भटनागर के बयानों के मुताबिक, इस संगठन का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि सीजेपी और उसके विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना है। उनका दावा है कि संगठन भविष्य की रणनीति तैयार करेगा और विभिन्न स्थानों पर छोटे-बड़े समूहों के माध्यम से अपनी बात रखेगा।

उन्होंने सीजेपी को खुली बहस की चुनौती भी दी है। उनके अनुसार, यदि विरोध करने वाले अपने विचारों को लेकर आह्वस्त हैं, तो उन्हें सार्वजनिक चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। यह घटनाक्रम केवल दो संगठनों के बीच टकराव की कहानी नहीं है। इसके पीछे लोकतांत्रिक विरोध, राजनीतिक लामबंदी, जनमत निर्माण और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद हैं। किसी संगठन का विरोध करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन उस विरोध की वैधता और प्रभाव का आकलन उसके नारों से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्यों, तथ्यों और तरीकों से किया जाना

जनगणना के नए नियमों पर विवाद जनगणना में संघ का हस्तक्षेप?

सनत जैन

भारत में जनगणना केवल आबादी गिनने की सरकारी प्रक्रिया नहीं है। देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय तस्वीर तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना है। इसी आंकड़े से सरकार की योजनाएं बनती हैं। संस्थाधनों का वितरण होता है। भविष्य की नीतियों की दिशा तय होती है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को लेकर विवाद खड़ा होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में 6 वर्ष की देरी के बाद अब 2027 की जनगणना के लिए नियमों में बदलाव ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। जनगणना भी अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ने 16 अक्टूबर 2026 को जनगणना नियम, 1990 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 के तहत किए गए इस बदलाव के अनुसार अब सरकारी संस्थानों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों, सोसायटियों, ट्रस्टों तथा विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों को भी गणना के काम में लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन जिसे उपयुक्त समझे, ऐसे व्यक्ति को भी गणनाकर्मी नियुक्त कर सकता है। सरकार का तर्क है, इतने विशाल देश में जनगणना के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी जुटाना बड़ी चुनौती है। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम है। ऐसे में केवल सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहने से शैक्षणिक कार्य और जनगणना के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर, सवाल यह है, कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए क्या चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं? कांग्रेस ने इस बदलाव पर गंभीर आपत्ति जताई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर और जनगणना

चाहिए।लोकतंत्र में असहमति को दबाने के बजाय उसे सुनना और समझना आवश्यक है। किसी सरकारी संस्था, संवैधानिक पदाधिकारी या राजनीतिक दल के फैसलों से असहमति होने पर नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, अपनी बात रखने और सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह, किसी प्रदर्शन से असहमत नागरिकों को भी अपनी राय व्यक्त करने तथा उसके विरोध में शांतिपूर्ण अभियान चलाने का अधिकार है।इस दृष्टि से लाल हिट जनता पार्टी’ का सामने आना विरोध की राजनीति के जवाब में एक दूसरे विचार के उभरने के रूप में देखा जा सकता है।

यदि एक समूह किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरे समूह को उस प्रदर्शन की आलोचना करने से रोका नहीं जा सकता। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति इसी बहुलता में निहित है, जहां अलग-अलग विचारों को सामने आने का अवसर मिलता है।लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब वैचारिक असहमति व्यक्तिगत आरोपों, अपमानजनक भाषा और एक-दूसरे को समाप्त करने की राजनीतिक मानसिकता में बदल जाती है। लोकतंत्र में किसी विचार का मुकाबला बेहतर तर्क से होना चाहिए, न कि केवल तीखे नारों और उतेजक नामों से। किसी संगठन की लोकप्रियता का वास्तविक आकलन इस बात से होगा कि वह जनता के सामने कौन-से तथ्य रखता है और जनहित के सवालों पर उसका दृष्टिकोण कितना स्पष्ट है।मीडिया रिपोर्टों में सीजेपी से जुड़े लोगों पर अराजकता फैलाने और विविध फंछिड़ प्राप्त करने जैसे आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। इन आरोपों को गंभीरता से देखा जा सकता है, लेकिन किसी भी आरोप को प्रमाण के बिना स्थापित तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा। यदि किसी संगठन की गतिविधियों, वित्तीय स्रोतों या प्रदर्शन के दौरान उसके आचरण को लेकर संदेह है, तो संबंधित तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी



चाहिए।लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता सभी संगठनों के लिए आवश्यक है। जो संगठन जनता के नाम पर आंदोलन करते हैं, उनसे यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे अपने उद्देश्यों, नेतृत्व, वित्तीय संसाधनों और गतिविधियों के संबंध में जवाबदेह रहें। लेकिन यही कसौटी उन संगठनों पर भी लागू होनी चाहिए जो विरोध प्रदर्शनों का प्रतिरोध करने के लिए सामने आते हैं।एक पक्ष पर लगाए गए आरोपों को दूसरे पक्ष की स्वतः निर्दीपता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

कानून का शासन इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जांच तथ्यों के आधार पर हो, न कि राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पर। यदि किसी संगठन को लेकर गंभीर शंकायत है, तो सक्षम संस्थाओं को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। आरोपों के आधार पर किसी समूह को दोषी घोषित करना न्यायपूर्ण लोकतंत्र की भावना के विपरीत है।अयान भटनागर ने सीजेपी को खुली बहस की चुनौती दी है। यह पहल अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकती है, बशर्ते बहस का उद्देश्य केवल एक-दूसरे को नीचा दिखाना न होकर जनता के सामने तथ्यों को स्पष्ट करना हो। लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद की संस्कृति कमजोर पड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक और वैचारिक समूह अक्सर विरोधी विचारों को सुनने के बजाय उन्हें पूरी तरह खारिज करने लगते हैं।यदि सीजेपी और लाल हिट जनता पार्टी’ के प्रतिनिधि किसी सार्वजनिक मंच पर

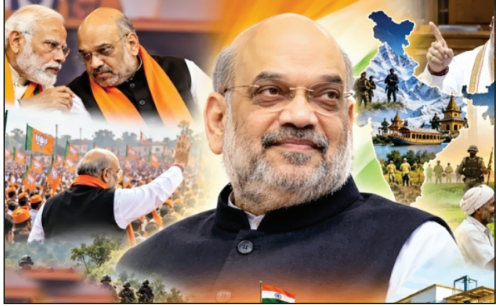
अमित शाह : संगठन, रणनीति व दृढ़ निश्चय के अद्वितीय शिल्पकार

सुरेश पत्नौरी

देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह की भारतीय राजनीति में पहचान एक ऐसे रणनीतिकार की है, जिन्होंने संगठन निर्माण, चुनावी प्रबंधन और राष्ट्रीय नीति निर्धारण के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबे अर्से से सामंजस््य बनाते हुए उन्होंने सत्ता और संगठन के बीच ऐसा समन्वय स्थापित किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की राजनैतिक यात्रा को नई दिशा मिली तथा चतुर्दिक व्यापक जनाधार प्राप्त हुआ। सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति की पहचान उसके पद से आगे बढ़कर उसके निर्णयों, संगठनात्मक क्षमता, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से निर्मित होती है।

भारतीय राजनीति में श्री अमित शाह की पहचान संगठन निर्माण, चुनावी रणनीति, प्रशासनिक निर्णयों और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों से जुड़ी रही है। प्रशासकी श्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उनकी राजनीतिक यात्रा ने राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। संगठनात्मक जिम्मेदारियों से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण दायित्वाें तक का उनका सफर उनकी राजनीतिक कार्यशैली, रणनीतिक सोच और नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं को सामने लाता है।

श्री अमित शाह से मेरी पहली मुलाकात का प्रसंग आज भी स्मृति पटल पर अंकित है। दिल्ली स्थित उनके निवास पर चर्चा के दौरान उनकी स्मरणशक्ति और सामाजिक-राजनैतिक विषयों की गहरी समझ ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनसे मिलकर मुझे जो सुखद अनुभूति हुई, उसका सार तत्व यह है कि उनकी कार्यशैली गहन अध्ययन और सुविचारित



रणनीति पर आधारित है।

श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह का वैचारिक समन्वय गुजरात से विकसित होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्लेखनीय सफलता ने श्री अमित शाह को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद विभिन्न राज्यों में पार्टी के विस्तार और चुनावी अभियानों के प्रबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही।

गुजरात से शुरू हुई श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह की बेमिसाल जोड़ी का राजनैतिक समन्वय आज राष्ट्रीय राजनीति में बानगी बन चुका है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नेतृत्व कौशल और जनविश्वास से व्यापक राजनैतिक आधार तैयार किया, वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संगठनात्मक विस्तार और चुनावी रणनीति के माध्यम से उसे मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री अमित शाह ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। सदस्यता अभियान का विस्तार, कार्यक्रमों की सक्रिय भागीदारी, नियमित जनसंपर्क और चुनावी तैयारियों

आमने-सामने बैठकर अपने विचार रखते हैं, तो जनता को दोनों पक्षों के तर्क समझने का अवसर मिल सकता है। ऐसी बहस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध के कारण, प्रदर्शन की वैधता, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सवाल, राजनीतिक दलों की भूमिका और सार्वजनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं।हालांकि, बहस केवल चुनौती देने से सफल नहीं होती। इसके लिए तथ्यात्मक तैयारी, संयमित भाषा और विरोधी पक्ष को सुनने की इच्छाशक्ति भी आवश्यक है। यदि दोनों समूह पहले से तय निष्कर्षों के साथ मंच पर आते हैं और केवल आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, तो उससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत, प्रमाणों और तर्कों पर आधारित संवाद लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है।अयान भटनागर ने यह भी दावा किया है कि प्रदर्शनों के कारण कारोबारियों का धंधा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित बदसलूकी का मुद्दा भी उठाया। इन शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन व्यापक सिद्धांत स्पष्ट है कि किसी भी आंदोलन के दौरान आम नागरिकों के अधिकारों और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।बाजारों में काम करने वाले व्यापारी, दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक, कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, मरीज और विद्यार्थी किसी भी राजनीतिक विवाद के प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं होते। यदि विरोध प्रदर्शनों के कारण यातायात बाधित होता है, दुकानों का कारोबार प्रभावित होता है या लोगों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है, तो इसका समाधान निकालना जरूरी है।इसका अर्थ यह नहीं कि कारोबार या यातायात में असुविधा का हवाला देकर हर प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाए। शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन प्रदर्शन के लिए उचित स्थान, समय और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा आयोजक कानून

के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा की कोई घटना होती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।अयान भटनागर का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फोन कर दें तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ सकते हैं, राजनीतिक लामबंदी की संभावनाओं की ओर संकेत करता है। लेकिन किसी नेता के आह्वान पर भीड़ जुट जाना और किसी विचार को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त होना दो अलग-अलग बातें हैं।भीड़ की संख्या किसी संगठन की वास्तविक सामाजिक स्वीकार्यता का एकमात्र प्रमाण नहीं हो सकती। जनसमर्थन का मूल्यांकन इस बात से भी होना चाहिए कि संगठन कितने समय तक सक्रिय रहता है, समाज के वास्तविक मुद्दों पर क्या योगदान देता है और अपने विचारों को कितनी स्पष्टता से प्रस्तुत करता है।

किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन की विश्वसनीयता उसके काम, व्यवहार और जवाबदेही से बनती है। यदि लाल हिट जनता पार्टी’ वास्तव में सीजेपी की गतिविधियों का वैचारिक प्रतिरोध करना चाहती है, तो उसे अपने उद्देश्यों और कार्ययोजना को स्पष्ट करना होगा। केवल किसी विरोधी संगठन के खिलाफ खड़ा होना स्थायी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जनता यह भी जानना चाहेगी कि संगठन लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों, चुनावी पारदर्शिता और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे सवालों पर क्या सोचता है।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में विचारों का टकराव स्वाभाविक है। यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष, सरकार समर्थक और सरकार विरोधी, तथा अलग-अलग सामाजिक समूहों को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है।

को व्यवस्थित करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा। पन्ना प्रमुख जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से संगठनात्मक जिम्मेदारियां निर्धारित करने की प्रक्रिया को विशेष महत्व मिला।

उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा ने देश के अनेक राज्यों में अपना आधार विस्तृत किया और सदस्यता के लिहाज से विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। यह उपलब्धि व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क, कार्यकर्ता-भागीदारी और निरंतर चुनावी सक्रियता का परिणाम थी और इस दूरदर्शी सोच के उन्नायक श्री अमित शाह थे।

केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और विधायी निर्णय हुए। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 से संबंधित प्रावधानों में बदलाव और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन ने देश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने वाला कानून तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम भी उनके कार्यकाल के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

भारत की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता की दृष्टि से लिए गये ये महत्वपूर्ण निर्णय और राष्ट्र हित में कड़ा-से-कड़ा निर्णय लेने की प्रमुख उपलब्धियों में शुमार हैं. आज हम देख रहे हैं कि मजबूत भारत बनाने की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

देश में आतंकवाद की जड़ों को समूल नष्ट करने, आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने,

वामपंथ प्रेरित उग्रवाद से मुकाबला करने, पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने में श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में कामयाब मिली। गृह मंत्री के रूप में वे अपने उत्तरदायित्व का जिस सक्षमता और दृढ़ता से निर्वहन कर रहे हैं, वह काबिल-ए-तारीफ है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और श्री अमित शाह के निर्देशन में विशेष सुरक्षा बलों, पुलिसकर्मियों के सफल प्रयासों से नक्सलवाद के दंश से देश को मुक्ति मिली है। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सुनियोजित नक्सल-विरोधी रणनीति सफल हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशन में एक सशक्त पहल करते हुए 31 मार्च, 2026 से नशे के खिलाफ तीन वर्ष का देशठ/यापी अभियान चलाने का लक्ष्य तय किया गया है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में भी श्री अमित शाह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत में सहकारिता आंदोलन का संबंध कृषि, दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण ऋण व्यवस्था और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों से रहा है। सहकारी संस्थाएं किसानों, छोटे उत्पादकों और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सफल माध्यम रही हैं।

श्री अमित शाह की राजनैतिक कार्यप्रणाली पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट है कि उनमें संगठनात्मक अनुशासन कायम रखने और राष्ट्र हित में कड़ा-से-कड़ा निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ उनका दीर्घकालीन वैचारिक समन्वय, भारतीय जनता पार्टी संगठन के व्यापक विस्तार में उनका योगदान और गृह मंत्री के रूप में उनके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय देशहित में रहे हैं।

अनियंत्रित भीड़ को शिव बारात की उपमा देकर राहुल ने हिंदू भावनाओं को पहुँचाई ठेस!

नीरज कुमार दुवे

भले ही राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में अपने राजनीतिक मार्च को ‘शिव बारात’ कहकर केवल एक उपमा दी हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवान शिव की बारात जैसे पवित्र धार्मिक प्रसंग को राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करना उचित था? जिस बारात की संबंध देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के दिव्य विवाह से है, उसे एक राजनीतिक आंदोलन का नाम देने समय क्या उसकी धार्मिक गरिमा और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए था? हम आपको याद दिला दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के मार्च के दौरान कहा था कि यह शिव की बारात है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। उन्होंने आंदोलन को तुलना भगवान शिव के तांडव से भी की थी। उनका आशय आंदोलन को तांडव:स्फूर्त और सबके लिए खुला बताना था। लेकिन इसी बयान ने धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल पर विवाद खड़ा कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने उनकी टिप्पणी की आलोचना करते हुए सार्वजनिक माफी की माँग की है। देखा जाये तो यहाँ सवाल केवल एक उपमा का नहीं, बल्कि उस धार्मिक प्रतीक के अर्थ का है जिसे भारतीय समाज में विशेष श्रद्धा के साथ देखा जाता है। राहुल गांधी को शायद पता नहीं कि शिव बारात कोई सामान्य जुलूस नहीं है। शिवपुराण की रूद्रसंहिता के

पार्वतीखंड में भगवान शिव की विवाह-यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। अध्याय 40 में शिव की बारात का प्रसंग है। इसके बाद विवाह की तैयारियों, शिव के हिमालय पहुंचने और विवाह-संस्कार का वर्णन आगे के अध्यायों में आता है। अध्याय 48 में पुरोहितों द्वारा तिथि आदि बताए जाने और शुभ समय आने के बाद विवाह-संस्कार प्रारंभ होने का उल्लेख है। शिव बारात का धार्मिक महत्त्व इसी दिव्य विवाह से जुड़ा है। इसमें शिवगणों, नंदी, देवताओं और ऋषियों की सहभागिता का वर्णन मिलता है। लोकपरंपरा में भूत-प्रेत और विचित्र रूप वाले गणों के चित्रण ने इस बारात को एक विशिष्ट पहचान दी है। यह शिव के उस स्वरूप की याद दिलाता है जो बाहरी रूप, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा की सीमाओं से परे है। इसीलिए शिव बारात को केवल लोगों की भीड़, नारेबाजी या किसी राजनीतिक आंदोलन के लिए सुविधाजनक उपमा मान लेना श्रद्धालुओं को असहज कर सकता है। धार्मिक प्रतीक की अपनी गरिमा होती है और उसका इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जा रहा है, यह महत्त्वपूर्ण है। साथ ही यहां यह सवाल भी उठता है कि क्या शिव बारात किसी भी दिन निकल सकती है? देखा जाये तो हिंदू धर्म में धार्मिक पर्व, विवाह-संस्कार और शोभायात्रा के अपने अलग-अलग नियम और परंपराएँ हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे प्रमुख पर्व है। इस अवसर पर देशभर में शिव बारात निकाली जाती है और शिव-पार्वती विवाह की झोंकियाँ सजाई जाती हैं।

विश्वकल्याण के लिए प्रतिबद्ध भारत का निर्माण: डॉ. मोहन भागवत

हेमन्‍द्र क्षीरसागर

नागपुर में 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव पर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का उद्बोधन भारतीय समाज के आत्मबोध, सांस्कृतिक अस्मिता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित रहा। संघ की शताब्दी के कार्यक्रमों के समिपान अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्वकल्याण के लिए प्रतिबद्ध भारत का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक उत्थान से संभव है।

सरसंघचालक के उद्बोधन का मूल स्वर अपनी सभ्यतागत पहचान को समझने और उसे समकालीन जीवन में उतारने का रहा। भारत की विविधता को कमजोरी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समपन्नता मानते हुए उन्होंने एक एकात्म भाव को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। जो विभिन्न मत-पंथों, भाषाओं, जातियों और प्रादेशिक पहचानों के बावजूद नागरिकों को एक सूत्र में बांधता है। संविधान की भावना के अनुरूप ‘हम भारत के लोग’ का बोध तभी सार्थक होगा। जब समान राष्ट्रीय हित, पारस्परिक सम्मान और कर्तव्यनिष्ठा हमारे व्यवहार में दिखाई दें। यही भाव स्वबोध से राष्ट्रबोध की ओर अग्रसर करता है।

संत रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष

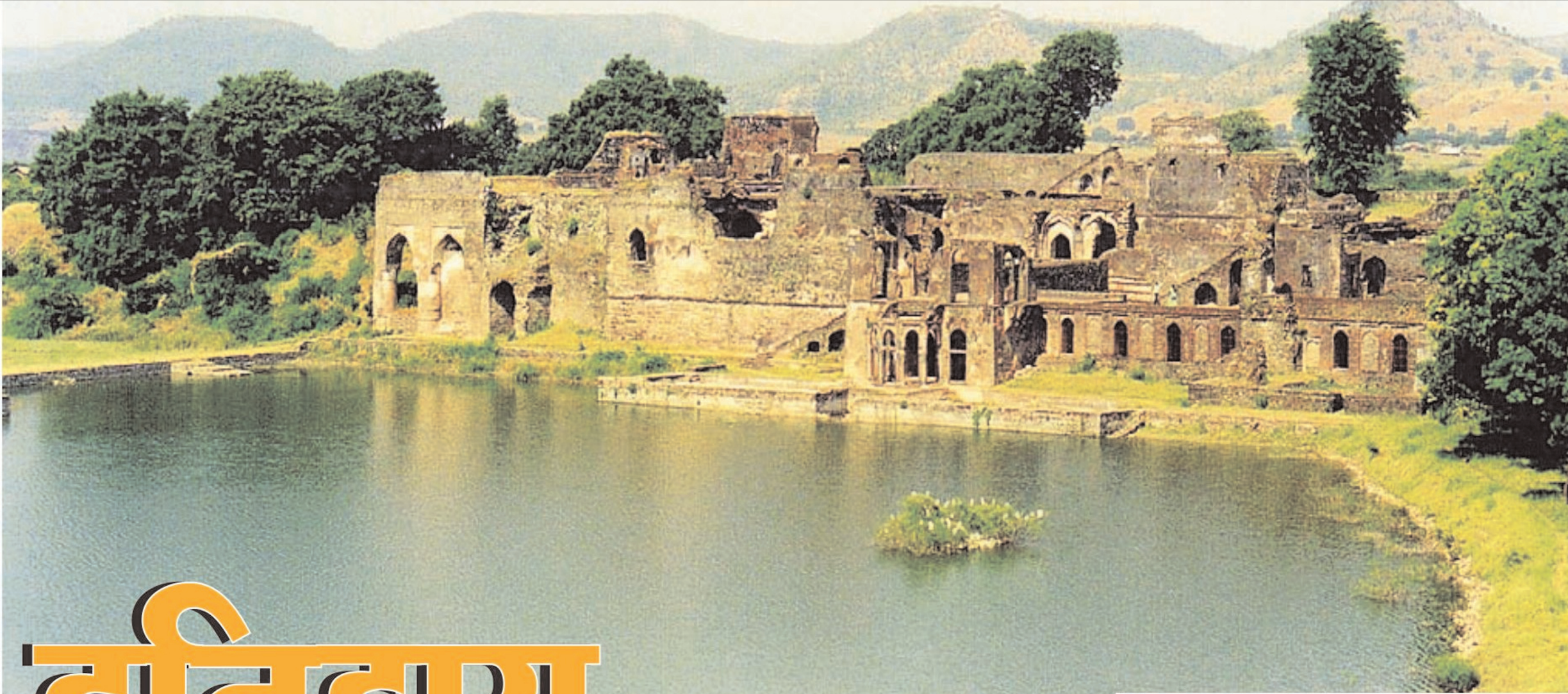


का संदर्भ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनका जीवन श्रम की प्रतिष्ठा, भक्ति, स्वधर्मनिष्ठा और सामाजिक समरसता की प्रेरणा देता है। स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों का स्मरण भी त्याग, सेवा और सांस्कृतिक चेतना के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देता है।

संघ के शताब्दी वर्ष में रेखांकित पंच परिवर्तन सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वबोध एवं स्वदेशी तथा नागरिक अनुशासन के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने सामाजिक जीवन की दिशा बदलने वाला व्यापक अभियान बताया। इनका वास्तविक महत्व तभी है, जब वे नारों और आयोजनों तक सीमित न रहकर दैनिक आचरण का हिस्सा बनें। परिवार में संस्कार, समाज में समानता, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। स्वदेशी के प्रति आग्रह और नागरिक कर्तव्यों का पालन राष्ट्रनिर्माण का आधारशिलाएं हैं।

विज्ञान, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति को स्वीकार करते हुए उद्बोधन में सरसंघचालक ने उनके विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया। तकनीक अपने आप में समाधान नहीं, उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य और नैतिक दृष्टि से किया जाता है। डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध सामग्री, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और नई पीढ़ी के सामने उपस्थित चुनौतियों के संदर्भ में परिवार, समाज और शासन की साझा जिम्मेदारी रेखांकित की। विकास का प्रतिमान ऐसा होना चाहिए, जिसमें आर्थिक समृद्धि के साथ पर्यावरणीय संतुलन, मानवीय गरिमा और सामाजिक उत्तरदायित्व भी सुरक्षित रहें।

डॉ. मोहन भागवत के उद्बोधन का महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक तनावों और आंदोलनों के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रहा। समस्याओं के समाधान के लिए संवाद, जनसहभागिता और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन आवश्यक है। मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, किंतु उन्हें मनभेद, द्वेष और सामाजिक विभाजन आवश्यक है। वास्तविक विजय तभी होगी, जब राष्ट्रीय एकता केवल विचार न रहकर प्रत्येक नागरिक के आचरण में प्रतिबिंबित हो।



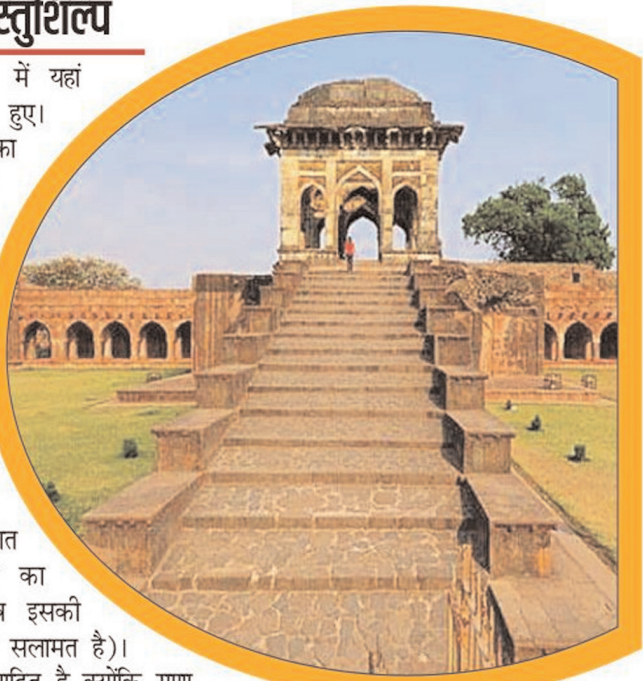
इतिहास और प्रेम का शहर माण्डू

माण्डू को रचने-बसाने का प्रथम श्रेय परमार राजाओं को है। हर्ष, मुंज, सिंधु और राजा भोज इस वंश के महत्वपूर्ण शासक रहें हैं। किंतु इनका ध्यान माण्डू की अपेक्षा धार पर ज्यादा था, जो माण्डू से महज 30 किलोमीटर है। परमार वंश के अंतिम महत्वपूर्ण नरेश राजा भोज का ध्यान वास्तु की अपेक्षा साहित्य पर अधिक था और उनके समय संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। मांडू प्राचीन शहर है और इसका जिक्र 555 ईसवी के संस्कृत अभिलेखों में भी है। इन अभिलेखों से पता चलता है कि मांडू छठी शताब्दी का खूबसूरत शहर हुआ करता था। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में परमार वंश के शासकों ने इस पर अधिकार किया और इसका नाम मांडवगढ़ रखा। 13वीं शताब्दी में परमारों ने अपनी राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित कर दी और इस शहर का महत्व बढ़ गया। 1305 में खिलजी वंश से पराजित होने के बाद परमारों का मांडू से आधिपत्य समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश के 21 वर्ग किलोमीटर तक फैले पठार पर बना मांडू, प्रेम के शहर के रूप में भी याद किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला और दक्षिणी इंदौर के पश्चिम में बसा हुआ है।

मुगलों के साम्राज्य के पतन के बाद मालवा के अफगान गवर्नर दिलावर खान ने मांडू को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद यानी खुशियों का नगर रखा। दिलावर खान गौरी के पुत्र हरशंग शाह ने मांडू का विकास किया और इसे संपन्न बनाया। यह युग मांडू का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद कई मुगल शासकों ने मांडू पर राज किया फिर 1732 में मराठों ने इस पर अधिकार कर लिया।

अद्वितीय वास्तुशिल्प

सुल्तानों के काल में यहां महत्वपूर्ण निर्माण हुए। दिलावर खां गौरी ने इसका नाम बदलकर सादियाबाद (आनंद नगरी) रखा। होशंगशाह इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। मुहम्मद खिलजी ने मेवाड़ के राणा कुम्भा पर विजय के उपलक्ष्य में अशरफी महल से जोड़कर सात मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण कराया (अब इसकी केवल एक ही मंजिल सलामत है)। हालांकि यह तथ्य विवादित है क्योंकि राणा कुम्भा ने भी मुहम्मद खिलजी पर विजय की स्मृति में चित्तौड़ के विश्व प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। आमतौर पर इतिहासकार मानते हैं कि राणा ने खिलजी को बंदी बनाया था और माफी पर उसे छोड़ा था। फिर भी फरिश्ता जैसे इतिहासकार मुहम्मद



खिलजी की वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। वह लिखता है कि खिलजी हमेशा युद्ध में रहता है। अशरफी महल का निर्माण मदरसे के तौर पर हुआ था और उसके कई कमरे आज भी काफी अच्छी अवस्था में हैं।

बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी

बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी की वजह से भी मांडू की अलग पहचान है। बाज बहादुर संगीतज्ञ थे जबकि रानी रूपमती गायिका थीं। वह रूपमती से गायिकी सीखना चाहते थे। कहा जाता है जब उन्होंने रानी रूपमती को जंगल में खान करते देखा तो उन पर फिदा हो गये। उन्होंने रूपमती को मांडू आने का न्यौता दिया लेकिन रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन करके ही गाना गाती थीं। इसलिए बाज बहादुर ने उनका आश्रय ऐसे स्थान पर बनाया जहां से नर्मदा नदी को आसानी से देखा जा सके। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में इसका नाम मांडवगढ़ था लेकिन बाद में इस शहर को सादियाबाद के नाम से भी जाना गया। समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा मांडू इतिहास और प्राकृतिक खूबसूरती के कारण प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। रूपमती के सौन्दर्य की चर्चा दूर-दूर तक फैल चुकी थी और इसी चर्चा से प्रभावित होकर अकबर ने मांडू पर आक्रमण कर दिया। इसकी भनक लगते ही रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बाद में बाज बहादुर अकबर के दरबार में संगीतज्ञ बन गये।

आल्हा-ऊदल के वीरता की कहानी

आल्हा-ऊदल के बिना माण्डू का वर्णन अधूरा माना जाता है। आल्हाखण्ड में महाकवि जगनिक ने 52 लड़कियों का जिक्र किया है। उसमें पहली लड़की माण्डूगढ़ की मानी जाती है, जिसका साम्य इसी माण्डू से किया जाता है। इसलिए आल्हा गायकों के लिए माण्डू एक तीर्थस्थल सरीखा है। बुंदेलखंड के लोग यहां इस लड़की के अवशेष देखने आते हैं। राजा जम्बे का सिंहासन, आल्हा की सांग, सोनगढ़ का किला, जहां आल्हा के पिता और चाचा की खोपड़ियां टांगी गई थी और वह कोल्हू जिसमें दशराज-वक्षराज को करिगा ने पीस दिया था। ये सब आज भी आल्हा के मुरीदों को आकर्षित करते हैं। 'माण्डू सिटी ऑफ जॉय' के लेखक गुलाम यजदानी के अनुसार माण्डू के भवन रोमन, ग्रीक, ईरानी, यूनानी, गैथिक, अफगान और हिंदू शैली से बने हैं। हिंदू शैली में बने भवन मुख्य हैं- हिण्डोला भवन, जामी मस्जिद, होशंगशाह का मकबरा आदि। पत्तियां, कमल के फूल, त्रिशूल, कलश, बंदनवार आदि इसके गवाह हैं। अफगान शैली में बने भवन हैं- रूपमती मण्डप, बाजबहादुर महल दरिया खां का मकबरा, जहाज महल आदि।



क्या देखें

सोलहवीं शताब्दी में बाज बहादुर द्वारा बनाया गया महल यहां के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है। इस महल की विशेषता यह है कि यहां से चारों तरफ का बेहतरीन नजारा नजर आता है। महल मुगल और राजस्थानी शैली का मिश्रित रूप है। इसके अलावा, यहां रूपमती मंडप भी स्थित है, जिसे सेना द्वारा नियंत्रित रखने के लिए बनवाया गया था। मंडप किले के बिल्कुल किनारे पर बना है। यहां की खासियत यह है कि यहां से नर्मदा नदी और उसके मैदानों का सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। यहीं मंडप रानी रूपमती का आश्रय स्थल था। मांडू की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक इमारत जहाज महल है। यह बिल्कुल पानी के जहाज के आकार का बना है। इसकी लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस महल के पश्चिम और पूर्व में दो झीलें भी हैं। मुंज तालाब और कपूर तालाब नामक इन झीलों से घिरा यह महल ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज बंदरगाह पर खड़ा हो। इस महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहां पहाड़ी की खड़ी ढाल पर नीलकंठ मंदिर स्थित है और आज भी श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना करते हैं। इसके अलावा, यहां हाथी महल, दरियाखान मकबरा, मांडू के 12 प्रवेश द्वार, हिंडोला महल, रीवा कुंड, चम्पा बावली, अशरफी महल, जैन मंदिर आदि ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल हैं, जिसे देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

कब जाएं

मांडू घूमने के लिए मानसून से बेहतर मौसम और कोई हो ही नहीं सकता। जुलाई से अगस्त तक मांडू घूमने के लिए उपयुक्त समय है। इस दौरान यहां की हरियाली और पानी से भरे हुए जलाशय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बारिश से धुल कर यहां की ऐतिहासिक इमारतें और भी साफ नजर आने लगती हैं।

कैसे पहुंचें

वायुमार्ग: मांडू जाने के लिए इंदौर नजदीकी एयरपोर्ट है। यह प्रमुख एयरलाइन्स द्वारा भोपाल, ग्वालियर, मुंबई, दिल्ली और जयपुर से जुड़ा है। इंदौर से मांडू की दूरी 99 किमी है। सड़क मार्ग से यहां तक पहुंचने में लगभग दो घंटे लगते हैं।

रेलमार्ग: यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन रतलाम और इंदौर है। यह इंदौर से 99 किमी. और रतलाम से 124 किमी. दूर है। इंदौर से मांडू बस या टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं।

सड़क मार्ग : इंदौर मांडू मार्ग नियमित रूप से बस से जुड़ा हुआ है। भोपाल से भी मांडू के लिए बसें चलती हैं।



जहाज महल

जहाज महल माण्डू का सर्वाधिक चर्चित स्मारक है। चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण यह जहाज का दृश्य उपस्थित करता है। इसकी आकृति टी के आकार की है। इसका निर्माण परमार राजा मुंज के समय हुआ किंतु इसके सुदृढीकरण का श्रेय गयासुद्दीन खिलजी को है। माण्डू की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अंतः भूगर्भीय संरचना है। माण्डू का फैलाव जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। शत्रु के आक्रमण के समय यह भूगर्भीय रचना सुरक्षा का एक साधन भी थी। यह संरचना अपने निर्माण से आज भी विस्मृत करती है। धार व माण्डू के बीच बने 35 भवन एक अन्य आश्चर्यजनक निर्माण हैं। ये भवन इको प्लाईट का काम करते थे। सुल्तान जब माण्डू से धार के लिए निकलता था तो इन्हीं भवनों से उसके आने की खबर दी जाती थी। माण्डू से कुछ दूरी पर बूढ़ी माण्डू स्थित है। इसे ऋषि माण्डव या माण्डवी के नाम पर सिद्धक्षेत्र कहा गया है।



लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज राजनांदगांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजनांदगांव जिले में स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं लंबित सड़कों, पुल-पुलियों तथा भवन निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पुराने एवं लंबित निर्माण कार्यों को आगामी दिसम्बर माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश के कारण रुके निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। विभागीय सचिव ने गुणवत्ताहीन एवं समय-सीमा में कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ब्लैक-लिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। राजनांदगांव के कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी बैठक में मौजूद थे।

विदेशी ताकतों संग मिलकर देश को अस्थिर कर रहे हैं राहुल

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भारत में विपक्ष के नेतृत्व में हो रहे विरोध-प्रदर्शन देश को अस्थिर करने की एक साजिश का हिस्सा हैं। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अमेरिकी सांसदों इल्हान उमर और रो खन्ना के साथ कथित संबंधों पर सवाल उठाए। साथ ही, उन्होंने विदेशी फंडिंग, क्रिप्टोकॉरेंसी और ऑनलाइन जुए को लेकर भी चिंता जताई। दुबे ने दावा किया कि विदेशी संगठन और कुछ लोग भारत में अस्थिर बदलने के लिए विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहा है, हालाँकि उन्होंने अपने इन दावों को साबित करने के लिए अपनी असहमति या विरोध कहाँ जताएंगे ? इसलिए, हमें लोगों के विरोध-प्रदर्शन और गतिविधियों के लिए जंतर-मंतर को वापस बहाल कराने के लिए लड़ना होगा।

सीजेपी के नेताओं सौरत और आशुतोष रंका की बढ़ी मुश्किलें

नईदिल्ली। तिहाड़ जेल से एक हफ्ते की न्यायिक हिरासत के बाद हाल ही में रिहा हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजकों-सौरव दास और आशुतोष रंका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली पुलिस की फ्राइम ब्रांच ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े दो मामलों में पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए दोनों नेताओं को औपचारिक समन जारी किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सीजेपी के सदस्य अजिंक्य शिंदे को भी समन भेजा गया है। यह जांच बिना अनुमति कहीं घुसने और किसी सरकारी अधिकारी के आदेश को अवहेलना करने के आरोपों से जुड़ी है। दास और रंका को गुरुवार दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित फ्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। यह समन तब आया है, जब ये दोनों नेता एक हफ्ते तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं।

सीजेपी के जेन-जी आंदोलन को दिलीप घोष ने बताया बड़ा घोटाला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से जुड़े जेन-जी आंदोलन को एक बड़ा घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होगा, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वह किसी भी नाम से काम कर रहा हो। सीजेपी कार्यकर्ताओं – सौरव दास और आशुतोष रंका – के जेन-जी का हिस्सा होने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों पर चल रही बहस के संदर्भ में, घोष ने कहा कि इस आंदोलन के उद्देश्य इसके सदस्यों के कामों से साफ हो रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए घोष ने कहा कि सीजेपी का जेन-जी आंदोलन एक बड़ा घोटाला है। लोग किसी एक मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा करते हैं और एक नाम का इस्तेमाल करते हैं। उनके काम से उनके मकसद साफ हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि उनके पीछे कौन है और वे क्या चाहते हैं। देश और दुनिया भी यह समझ चुकी है।

इंडिया गठबंधन पर जनता दल यूनाइटेड का हमला

नईदिल्ली। जनता दल (यूनाइटेड) ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के औचित्य पर बृहस्पतिवार को सवाल उठाया और कहा कि इसके घटक दल राज्य विधानसभा चुनावों में अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और उनके बीच नेतृत्व, मुद्दों या मिलकर चुनाव लड़ने की योजना को लेकर कोई सहमति नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं की बृहस्पतिवार शाम को ऑनलाइन बैठक होने वाली है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शनों की रूपरेखा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दबाव बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मल्लिकार्जुन खरगे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें एक नवंबर को दिल्ली में होने वाली ‘इंडिया’ गठबंधन की रैली की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि सरकार महिला आरक्षण अधिनियम को जल्द लागू करने के लिए परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के वास्ते संसद का सत्र बुला सकती है।

केंद्रीय गृहमंत्री का राहुल गांधी को मैसेज

अगले 30 साल आपका नंबर नहीं लगने वाला : शाह

नईदिल्ली। ऐसे समय में जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं और कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता पर एक और निशाना साधा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कांग्रेस पार्टी अगले तीन दशकों तक सत्ता से बाहर रहेगी। यमुना की सफाई के लिए 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद, शाह ने गांधी की विदेश यात्रा पर तंज कसा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद चार दिन की यात्रा पर वियतनाम गए हैं। शाह ने कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे सुन नहीं सकते, आप विदेश में कहीं बैठे हैं। आप यह भी नहीं बताते कि क्यों, लेकिन कोई बात नहीं, यह आपकी निजी जिंदगी है... लेकिन जब आप दिल्ली लौटें, तो मेरी बात सुन लें; अगले तीस सालों तक आपकी बारी नहीं आएगी।

गांधी का वियतनाम जाना ऐसे समय में हुआ है जब इंडिया गठबंधन और कॉकरोच जनता पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन स्क्रूक्र प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और उनमें ज्ञानेश कुमार की कथित भूमिका को लेकर हो रहे हैं। हमेशा की तरह, बीजेपी ने उनके इस विदेश दौर को लेकर उन पर तुरंत तंज कसा। भगवा पार्टी ने गांधी परिवार के सदस्य पर आरोप लगाया कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान झूठ बोल-बोलकर



थक जाने के बाद वे छुट्टियां मनाने चले गए हैं। पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वे कथित तौर पर तंज कसा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद चार दिन की यात्रा पर वियतनाम गए हैं। साथ ही, पार्टी ने सवाल किया, राहुल गांधी के विदेशी दौरों का एजेंडा क्या है?

बीजेपी नेता संवित पात्रा ने गांधी पर सत्ता परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि वे जॉर्ज सोरोस से क्लास लेने के लिए विदेश गए थे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस नेता विदेश छुट्टियां मनाने गए थे या अपने अराजकता फैलाने वाले साथियों से मिलने। शाह ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप उठाया कि क्या कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कई राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर रहे हैं। उन्होंने कहा विरोध-प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होता। आप जहां से चुने गए हैं, वहां के लिए कोई योजना लेकर आए।

खेल प्रमुख समाचार

एशियाई पैरा खेलों के डिस्कस में सुवर्ण ने जीता स्वर्ण

नागोया। यहां जारी एशियाई पैरा खेलों में



भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया है। डिस्कस श्रो में सुवर्ण राज ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं तीरंदाजी में स्वाति चौधरी को रजत पदक मिला है। महिलाओं की डिस्कस श्रो एफ54 इवेंट में सुवर्ण ने 15.66 मीटर का शानदार श्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने छह प्रयासों में से पांच में 15 मीटर का निशान पार किया, जिससे उनका स्वर्ण पदक पक्का हो गया। वहीं इस स्पर्धा में ईरान की शाहला हदीदी ने 15.45 मीटर श्रो कर रजत पदक हासिल किया जबकि वियतनाम की थी न्गोक थ्यू गुयेन ने 14.65 मीटर के साथ ही तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता।

स्वर्ण विजेता सुवर्णा ने अब तक तीन एशियाई पैरा खेलों के साथ ही कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की ओर से खेला है। वह अभी एफ54 डिस्कस श्रो श्रेणी में एशिया में दूसरे नंबर पर हैं। गौरतलब है कि एफ54 क्लासिफिकेशन उन प्रतिस्पर्धियों के लिए है जिन्हें धड़ और निचले अंगों के काम करने में मुश्किलें आती है। इसलिए ये व्हीलचेयर पर बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरी ओर रजत विजेता स्वाति चौधरी ने महिलाओं की डब्ल्यू। इंडिविजुअल तीरंदाजी में रजत पदक जीतकर अहम उपलब्धि हासिल की है। यह इस श्रेणी में भारत का रजत पदक है, जो स्वाति की असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को दिखाता है। फाइनल मुकाबले में स्वाति ने चीनी प्रतिद्वंद्वी मिंगकान सेन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः 4-6 से हारकर उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। डब्ल्यू। श्रेणी उन एथलीटों के लिए है जिन्हें चारों अंगों में गंभीर विकार होते हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों और बड़े अंतरराष्ट्रीय ट्रायल्स के लिए कम समर्थन के बावजूद, स्वाति ने लगातार विश्व स्तरीय प्रदर्शन कर अपने को साबित किया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 460 अंक फिसला निफ्टी 22,687 पर बंद

मुंबई। शेयर बाजार में आज 22 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 460.30 अंक (0.62%) गिरकर 73,249.39 पर आ गया। वहीं, निफ्टी 123.70 अंक (0.54%) टूटकर 22,687.65 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से पावरग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, ट्रेड, बजाज फिनसर्व, इंडियो और हिंदुस्तान स्नैलिन्वर के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। गिरावट की 3 बड़ी वजहें हैं। पश्चिमी एशिया में तनाव से कच्चे तेल में उछल। सेंसेक्स डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी से बड़ी हलचल। ऑटो, एफएमसीजी और मेटल शेयरों में भारी बिकवाली।

केंद्र ने टेलीकॉम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स नियम को दी मंजूरी

नई दिल्ली। भारत को ग्लोबल टेक लीडर बनाने और टेलीकॉम सेक्टर में नए आविष्कारों को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर टेलीकम्युनिकेशंस (रेगुलेटरी सैंडबॉक्स) नियम, 2026 को नोटिफाई यानी मंजूर कर दिया है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद अब देश के युवा स्टार्टअप, बड़ी कंपनियां, रिसर्चर्स और आम वैज्ञानिक भी टेलीकॉम क्षेत्र की बिस्कुल नई तकनीकों, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल्स का लाइव ट्रायल कर सकेंगे। जब भी कोई कंपनी इंटरनेट, कॉमिंग या किसी नई टेलीकॉम टेक्नोलॉजी (जैसे 6त या एडवांस्ड 5एआई) पर काम करती है, तो उसे बाजार में लाने से पहले कड़े सरकारी नियमों से गुजरना पड़ता है। कई बार सख्त नियमों की वजह से नए आविष्कार रुक जाते हैं।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली। भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, ड्रिंका तथा इंस्टेंट कॉफी पर शुल्क समाप्त होने से भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में बढ़ावा मिलने की काफी संभावनाएं हैं। उद्योग निकाय टीपीसीआई ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। ब्रिटेन के सालाना 50.68 अरब अमेरिकी डॉलर के आयात में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.6 प्रतिशत है। भारत और ब्रिटेन ने व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई को व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीडीए) को लागू किया था। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद ने ब्रिटेन-भारत व्यापार परिषद के साथ एक समझौता किया है। टीपीसीआई के अनुसार, इस रणनीतिक समझौता ज्ञापन के तहत संस्थागत कारोबारी सहयोग के लिए एक समर्पित रूपरेखा तैयार की गई है।

मासिक ‘जीएसटी रिटर्न फॉर्म’ में बदलाव की तैयारी

नईदिल्ली। वित्त मंत्रालय मासिक ‘जीएसटी रिटर्न फॉर्म’ में प्रस्तावित बदलावों पर एक नवंबर से कारोबारियों की राय मांगेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के जीएसटी नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह ने कहा कि विभाग जीएसटी ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में भी काम करेगा। केंद्र एवं राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में जीएसटी रिटर्न (कर वापसी) में देनदारियों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में संशोधन के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य विसंगतियों को कम करना और नोटिस या सूचना भेजने की जरूरत घटाना है।

भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 23-25 अक्टूबर-क्या बदलेगी वैश्विक चावल अर्थव्यवस्था?

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के हर देश की अर्थव्यवस्था में खाद्य महंगाई, जलवायु परिवर्तन, परिवहन लागत और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की अनिश्चितता ने सरकारों से लेकर व्यापारिक संस्थानों तक की चिंता बढ़ा दी है।चावल और चीनी जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सीधे आम परिवारों के बजट पर पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा कि इसी बीच भारत 23,24 और 25 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम,प्रगति मैदान में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस (बिर्क2026) के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है।यह आयोजन केवल चावलकी प्रदर्शनी नहीं।बल्कि कृषि,खाद्य सुरक्षा, निर्यात,तकनीक,बैंकिंग,लॉजिस्टिक्स और वैश्विक व्यापार के परस्पर संबंधों को समझने का महत्वपूर्ण मंच है।आधिकारिक सम्मेलन

वेबसाइट के अनुसार,इसमें 120 से अधिक देशों की भागीदारी और 30,000 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

साथियों बात अगर हम चावल की महंगाई- कीमतों में आग के पीछे कौन-से कारण ?इसको समझने की करें तो भारत में चावल की कीमतों का विश्लेषण करते समय सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सभी किस्मों के भाव एक समान नहीं होते।बासमती,सामान्य गैर- बासमती सोना मसूरी,पोन्नी, महौन और सुपर-फाइन चावल की कीमतें उनकी गुणवत्ता,उत्पादन क्षेत्र, मांग, ब्रांड, पैकेजिंग और परिवहन लागत के अनुसार अलग- अलग रहती हैं।दक्षिण भारत के कुछ बाजारों में 25 किगोलाम की चावल की बोरी के 1,450 रूपए से बढ़कर 1,850- 2,000 रूपए तक पहुंचने तथा चेन्नई में कुछ विशेष किस्मों के भाव बढ़ने के आंकड़े बाजार संबंधी दावों के रूप में सामने आए हैं।



हालांकि,इन सभी आंकड़ों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें पूरे देश में लागू मूल्यवृद्धि नहीं माना जाना चाहिए।यदि किसी बोरी की कीमत 1,450 रूपए से बढ़कर 1,850 रूपए होती है, तो वृद्धि लगभग 27.6 प्रतिशत बैठती है; 2,000 रूपए होने पर यह लगभग 37.9 प्रतिशत होगी। इसलिए किसी विशेष किस्म या बाजार में हुई तेजी को बिना व्यापक मूल्य-आंकड़ों के देशभर में चावल के दाम 50.0 प्रतिशत बढ़ जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।कीमतों में तेजी के संभावित कारणों में फसल की उत्पादकता मानसून और वर्षा

का असमान वितरण, कीटों का प्रभाव, त्योहारी मांग, भंडारण,मिलिंग लागत तथा परिवहन शामिल हैं।

अल- नीनो जैसी जलवायु परिस्थितियों का संभावित प्रभाव भी कृषि उत्पादन के आकलन में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन किसी एक मौसम घटना को कीमतों में वृद्धि का निश्चित कारण बताने के लिए कृषि उत्पादन के आधिकारिक आंकड़ों की जरूरत होती है। इसी प्रकार, जमाखोरी की आशंका की जांच वास्तविक स्टॉक, थोक- खुदरा मूल्य और और बाजार निरीक्षण के आधार पर होती चाहिए।

मोडिया के आंकड़ों में उपलब्ध कराई गई जानकारी में सरकार के पास लगभग 38 मिलियन टन चावल और निर्धारित बफर मानक करीब 10 मिलियन टन होने का उल्लेख है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के संदर्भ में भारतीय व्हाइट राइस का लगभग 385 डॉलर प्रति टन और वैश्विक भाव 420 डॉलर प्रति टन होने

का दावा भी प्रस्तुत किया गया है। यदि दोनों कीमतें समान गुणवत्ता, समान व्यापारिक शर्तों और समान अवधि पर आधारित हों, तो भारतीय भाव लगभग 8.3 प्रतिशत कम बैठता है।लेकिन अलग- अलग किस्मों, गुणवत्ता और निर्यात शर्तों के भावों की सीधी तुलना से बचना चाहिए।

साथियों बात अगर हमचीनी की कीमतों पर बड़ा फैसला 19 अक्टूबर की एथेनाल नीति क्यों महत्वपूर्ण ? इसको समझने की करें तो,चावल के साथ चीनी बाजार भी इस समय आर्थिक चर्चा के केंद्र में है।19 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2026-27 आपूर्ति वर्ष के लिए तेल विपणन कंपनियों की एथेनाल खरीद में गन्ने के रस,शुगर सिरप और बी-हेवी शीरे से बने एथेनाल को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है।इसका उद्देश्य घरेलू चीनी की उपलब्धता को सुरक्षित रखना और कीमतों पर दबाव कम करना है।

